छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

RNI Reg. No.-CHHHIN/2009/36148
डाक पंजीयन क्र.-45/Surguja Dn/2024-26

वर्ष - 17 ■ अंक - 295 ■ अम्बिकापुर, शनिवार 21 नवम्बर 2026 पृष्ठ -8 ■ मूल्य - 1 रूपये

WWW.cgfrontline.com

सरकार प्रदेश को नशे में डुबो रही है - भूपेश बघेल

छ.ग. फ्रंटलाइन जीपीएम। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौरेला में प्रेस वार्ता में राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आबकारी नीति, फसल नुकसान, रकबा कटौती, केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई और मतदाता सूची से नाम काटे जाने को लेकर सरकार को घेरा।

आबकारी नीति पर हमला

बघेल ने कहा कि कंपोजिट व्यवस्था के नाम पर सरकार ने



शराब दुकानों की संख्या दोगुनी से अधिक कर दी है। उनकी सरकार दुकानें कम कर रही थी, जबकि वर्तमान सरकार ने बंद दुकानें खोलने के साथ 60 से 66 नई दुकानें बढ़ा दीं। सूखे नशे के कारोबार में प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए उन्होंने कार्रवाई न होने की बात कही।

ईडी-सीबीआई पर बोले

सत्ता से हटने के तीन साल बाद भी उन पर और परिवार पर कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा, यदि पूर्व मुख्यमंत्री और उनका परिवार पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दिल-दिमाग में बसा है, तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। जांच एजेंसियों के डर से हर साल लाखों उद्योगपति देश छोड़ रहे हैं।

फसल नुकसान और रकबा कटौती

बेमौसम बारिश से फसल नुकसान पर सरकार किसानों के साथ खड़ी नजर नहीं आ रही। पटवारियों की हड़ताल और थर्ड पार्टी सर्वे से हजारों किसानों का रकबा कम या शून्य दिखाया गया। बघेल ने पूछा, मानवीय त्रुटि में रकबा घटाया ही क्यों गया, बढ़ाया क्यों नहीं गया। धान के खेत में मक्का और बरसात में धनिया दर्ज होने से किसान धान नहीं बेच पाएंगे और कर्ज संकट गहराएगा।

मतदाता सूची पर आरोप

देश में 13 करोड़ से अधिक और छत्तीसगढ़ में करीब 25 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए। इसमें बड़ी संख्या आदिवासी, दलित और विवाहित महिलाओं की है, जिन्हें 2003 के रिकॉर्ड के नाम पर परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस 26 नवंबर को संविधान दिवस पर सभी प्रदेश मुख्यालयों में 'वोट बचाओ, देश बचाओ' अभियान के तहत रैली करेगी। प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, पूर्व विधायक शैलेश पांडे, के.के. ध्रुव, जिला अध्यक्ष गजमती भानु सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

25 करोड़ वसूली केस में पुलिस को झटका, हाईकोर्ट ने शोएब की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

छ.ग. फ्रंटलाइन रायपुर। कांग्रेस नेता आनंदमल कुकरेजा से 25 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी शोएब ढेबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उसकी दोबारा गिरफ्तारी के लिए सीजेएम और एडीजे कोर्ट की ओर से जारी आदेशों पर रोक लगा दी है। जस्टिस पीपी साहू की एकल पीठ ने सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने 27 सितंबर को रिमांड कोर्ट की ओर से दिए गए जमानत के फैसले को सही माना है। इस मामले में रिमांड कोर्ट ने शोएब की गिरफ्तारी को गलत मानते हुए उसे जमानत दे दी थी। पुलिस ने इस फैसले को चुनौती दी थी। इसके बाद सीजेएम कोर्ट ने गिरफ्तारी को वैध ठहराते हुए जमानत का आदेश रद्द कर दोबारा गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। सीजेएम कोर्ट के बाद एडीजे कोर्ट ने भी शोएब की दोबारा गिरफ्तारी के आदेश जारी किए थे। अब हाईकोर्ट ने दोनों अदालतों के इन आदेशों पर रोक लगा दी है। साथ ही रिमांड कोर्ट के जमानत देने के फैसले को सही माना है।

विदेशी नंबर से धमकी देकर मांगे थे 25 करोड़

मामला रायपुर के तेलीबांधा थाने में दर्ज एफआईआर से



जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक, कांग्रेस नेता आनंदमल कुकरेजा को विदेशी नंबर से वॉट्सऐप पर धमकी भरे मैसेजेस भेजे गए थे। इन मैसेजेस के जरिए उनसे 25 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। जांच के बाद पुलिस ने शोएब ढेबर को आरोपी बनाया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए रायपुर कमिश्नरेट ने इनाम भी घोषित किया था। सूचना देने वाले को नकद इनाम देने की घोषणा की गई थी।

गिरफ्तारी के बाद पहचानने से किया इनकार, रिमांड कोर्ट ने दी जमानत

पुलिस कमिश्नरेट ने अक्टूबर में तकनीकी सबूत मिलने का दावा करते हुए शोएब ढेबर को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की सूचना जिस युवक को दी थी, वह कोर्ट में पेश हुआ और उसने शोएब को पहचानने से इनकार कर दिया। इसके अलावा गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेजों में भी खामियां मिली थीं। इन खामियों के आधार पर रिमांड कोर्ट ने पुलिस का रिमांड आवेदन खारिज कर दिया था। कोर्ट ने 27 सितंबर को शोएब को जमानत दे दी थी। हालांकि, इसके अगले दिन तेलीबांधा पुलिस ने दोबारा गिरफ्तारी के लिए आवेदन दिया। इस पर सीजेएम कोर्ट ने गिरफ्तारी को सही मानते हुए पहले का जमानत आदेश रद्द कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने शोएब को दोबारा गिरफ्तार करने की कार्रवाई शुरू की।

एआईसीसी के फेरबदल में देवेंद्र यादव बाहर, बंछोर की पोस्ट ने छेड़ी नई बहस

छ.ग. फ्रंटलाइन रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बार फिर अंदरूनी खींचतान और गुटबाजी को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा राष्ट्रीय सचिवों की नई सूची जारी किए जाने के बाद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को उनके पद से मुक्त कर दिया गया है। कांग्रेस के इस संगठनात्मक फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी रहे मनीष बंछोर ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट साझा की है, जिसने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को लेकर नई बहस छेड़ दी है। मनीष बंछोर ने



कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिवों की नई सूची साझा करते हुए लिखा, %बाप तो बाप रहेगा, जिस डाल पर बैठे उसी को काटोगे तो गिरना तय है.. इति सिद्धम..% इस टिप्पणी को भिलाई विधायक देवेंद्र यादव से जोड़कर देखा जा रहा है। मनीष बंछोर ने अपनी पोस्ट में सीधे तौर पर देवेंद्र यादव का नाम नहीं लिया है।

81 सचिवों को मिली जिम्मेदारी, 25 को छुट्टी

कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को संगठन में व्यापक फेरबदल करते हुए विभिन्न राज्यों और संगठनात्मक विभागों के लिए नए राष्ट्रीय सचिवों की नियुक्ति की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मंजूरी के बाद पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से नियुक्तियों की जानकारी दी गई। इस बदलाव में कुल 81 सचिवों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि 25 सचिवों और संयुक्त सचिवों को उनकी मौजूदा जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया है। इनमें छत्तीसगढ़ के भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का नाम भी शामिल है। पार्टी के इस निर्णय को राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक पुनर्गठन का हिस्सा बताया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसे लेकर अलग-अलग राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं।

एमसीबी में तेंदुए ने 14 वर्षीय लड़की का किया शिकार, धान कटाई कर लौट रही थी घर, माता-पिता चल रहे थे आगे

छ.ग. फ्रंटलाइन बैकुंठपुर। एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ वनमंडल के कोटाडोल परिक्षेत्र में वन्य प्राणी के हमले में 14 वर्षीय एक किशोरी की मौत हो गई। वह धान कटाई कर अपने माता-पिता के साथ देर शाम घर लौट रही थी। माता-पिता आगे-आगे तथा वह पीछे थी। इसी बीच अचानक तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। तेंदुए या बाघ द्वारा हमला करने का संदेह जताया जा रहा है। हालांकि वन अमले ने मौके पर पगमार्क की जांच की, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की संचालक का कहना है कि यह पगमार्क तेंदुए का हो सकता है। जांच जारी है। एमसीबी जिले के कोटाडोल विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मनियारी निवासी 14 वर्षीय रेखा 18 नवंबर को अपने माता-पिता के साथ धान की कटाई करने खेत में गई थी। धान कटाई करने के बाद देर शाम करीब 7 बजे सभी घर लौट रहे थे। किशोरी के माता-पिता आगे चल रहे थे, जबकि वह पीछे से आ रही थी। इसी बीच अचानक वन्य प्राणी ने किशोरी पर हमला कर दिया। उसने शोर मचाया, जब तक माता-पिता पहुंचे, उसकी मौत हो चुकी



थी। अंधेरा होने के कारण माता-पिता समेत अन्य हमला करने वाले वन्य प्राणी को देख नहीं पाए। दूसरी ओर वन्य प्राणी के हमले में बालिका की मौत के बाद गांव में भय का माहौल है। बताया जा रहा है कि घटना के अगले दिन पीड़ित परिवार ने कोटाडोल थाने में शिकायत दर्ज कराई।

फुट प्रिंट भेजा उच्चाधिकारियों को

वन्यप्राणी के हमले में मौत की जानकारी किशोरी के माता-पिता द्वारा वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही वन अमला मौके पर पहुंचा और जांच पड़ताल शुरू की। साथ ही पगमार्क की फोटो खींचकर डीएफओ मनेंद्रगढ़, संचालक गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व बैकुंठपुर को भेजी गई। लेकिन पगमार्क स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि घटना स्थल के आसपास क्षेत्र में कुछ दिन पहले बाघ का विचरण हुआ था। ऐसे में बाघ द्वारा हमला किए जाने की आशंका जताई जा रही है।

तेंदुए का हो सकता है फुट मार्क

गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व बैकुंठपुर की संचालक श्वेता कंबोज ने कहा कि घटना स्थल रेगुलर वनपरिक्षेत्र कोटाडोल है। वहां से हमें पगमार्क की फोटो भेजी गई है। इसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। परीक्षण के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। तेंदुआ का पग मार्क हो सकता है।

नवजात को बेचने वाले बड़े गिरोह का खुलासा, 3 डिलीवरी पर 26 जन्म प्रमाणपत्र, डॉक्टर समेत 3 गिरफ्तार

छ.ग. फ्रंटलाइन रायपुर। गुढ़ियारी के दिवाकर अस्पताल में नवजात बेचने का रैकेट चल रहा था। पुलिस ने डॉक्टर खिर सिंधु महानंद, नर्स प्रकाश कुमार कौरव और कृतिका के लिव-इन पार्टनर अश्विनी शर्मा को गिरफ्तार किया है। अस्पताल में जनवरी से अब तक सिर्फ 3 डिलीवरी हुईं, लेकिन 26 जन्म प्रमाणपत्र बने।

123 बच्चों की खरीद-फरोख्त का आरोप

आरोपी इस 11 महीने की अवधि में 23 बच्चों की खरीद-फरोख्त कर चुके हैं। पुलिस प्रकरण की जांच में आने वाले दिनों में नवजात की अवैध खरीद-फरोख्त में शामिल और आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कह रही है। पुलिस ने डॉक्टर खिर सिंधु के साथ पुरुष नर्स



प्रकाश कुमार कौरव, कृतिका के लिव इन पार्टनर अश्विनी शर्मा को गिरफ्तार किया है। इसके पूर्व घटना में शामिल तथा नवजात खरीद फरोख्त की मास्टर माइंड कृतिका साहू, अहिल्या नामदेव तथा गीतिका नाग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

ऐसे खुला पूरा कांड-आरोपियों ने ओडिशा, सुंदरगढ़ की गर्भवती महिला को मुफ्त में डिलीवरी कराने का झांसा देकर रायपुर में उनकी डिलीवरी कराई और नवजात का आठ लाख रुपए में सौदा किया था। नवजात को बेचने से इनकार करने पर आरोपियों ने महिला को बंधक बनाकर उससे पैसों की मांग कर रहे थे। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने इस गैंग को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है।

सौ से ज्यादा नवजातों की खरीद फरोख्त की आशंका-आरोपियों द्वारा तीन से चार साल के बीच सौ से ज्यादा नवजातों की खरीद-फरोख्त करने की पुलिस को आशंका है। पुलिस ने अभी इस एक साल की अस्पताल के रिकॉर्ड की जांच की है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल कर उनसे और पूछताछ कर रही है।

गुजरात से लेकर कई राज्यों में नवजातों की बिक्री-आरोपियों ने नवजातों की बिक्री गुजरात के अहमदाबाद, राजस्थान के अलग-अलग शहरों के साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना सहित कई राज्यों में की है। नवजात को छोड़ने प्रकाश, अश्विनी के अलावा कृतिका जाती थी।

गिरफ्तार आरोपियों की भूमिका-डॉक्टर खिर सिंधु बिना भर्ती किए ही फर्जी डिस्चार्ज टिकट बनाकर कृतिका को देता था। प्रकाश कुमार कौरव, अश्विनी शर्मा कमजोर महिलाओं को भर्ती कराते थे, सौदा कर रकम बांटते थे। अश्विनी लेन-देन संभालता था।

दुबई तक फैला ऑनलाइन सट्टा गिरोह, पुलिस के रडार पर करोड़ों की संपत्ति

छ.ग. फ्रंटलाइन बिलासपुर। शहर में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे और हवाला के जरिए करोड़ों रुपए का अवैध कारोबार करने वाले नेटवर्क का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि सट्टे से कमाई गई रकम हवाला के जरिए देश के अलग-अलग राज्यों में भेजी गई। इस रकम से करीब 25 करोड़ रुपए की संपत्तियां बनाई गईं। नेटवर्क के तार दुबई तक जुड़े हैं और वहां भी संपत्ति होने की जानकारी मिली है। पुलिस ने 13 नवंबर को संदिग्धों के ठिकानों पर छापा मारकर करीब 8 लाख रुपए कैश, सोने के गहने, महंगी घड़ियां और बैंकिंग दस्तावेज जब्त किए हैं। तलाशी में 25 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। पुलिस अब इन संपत्तियों के स्रोत का पता लगाकर कुर्की की तैयारी कर रही है। आरोपियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है। विदेश में मौजूद संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। मामले में सुनील रोहरा, मनीष रोहरा और जबलपुर निवासी आकाश गोगा जांच के दायरे में हैं। मामले की जांच सिटी कोतवाली में दर्ज अपराध क्रमांक 229/2026 के तहत की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे से मिलने वाली रकम को हवाला के जरिए अलग-अलग जगह भेजा जाता था। इस रकम का इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने में किया गया। जांच में देश के कई राज्यों में सट्टे की रकम के लेन-देन की जानकारी मिली है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के आर्थिक लेन-देन की जांच कर रही है।

अकवान तूफान का असर, रायपुर में बूंदाबांदी, अंबिकापुर में 7.6 डिग्री तक गिरा पारा

छ.ग. फ्रंटलाइन रायपुर। चक्रवाती तूफान अकवान के असर से छत्तीसगढ़ का मौसम बदल गया है। रायपुर में गुरुवार रात करीब 11 बजे के बाद ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे लोग अलाव तापते नजर आए। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 7 जिलों बलरामपुर, जांजगीर-चांपा, जशपुर, रायगढ़, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़ और सरगुजा में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। पेंड्रा में भी सुबह से रुक-रुककर बारिश हो रही है।

बंगाल की खाड़ी में बना है चक्रवाती तूफान

तूफान अकवान आज दोपहर उत्तरी आंध्र प्रदेश



और दक्षिणी ओडिशा के तट से गोपालपुर के पास टकरा सकता है। इस दौरान 90 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, झोंके 110 किमी तक पहुंच सकते हैं।

प्रदेश में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

मौसम विभाग ने प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं, एक-दो स्थानों पर भारी बारिश के साथ गरज-चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई है।

रायपुर में सामान्य से कम रहा तापमान

मौसम विभाग के 19 नवंबर के आंकड़ों के मुताबिक, रायपुर में अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.6 डिग्री कम रहा। इस तरह दिन और रात के तापमान में 12.5 डिग्री का अंतर दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 7.6 डिग्री और सबसे अधिक अधिकतम तापमान दुर्ग में 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

(बालाजी क्लीनिक)
मद्रासी दवाखाना
Reg. No. Cg03026 ISO 9001: 2015 CERTIFIED

बादी एवं खूनी बवासीर, नासूर, भगंदर, फीसर एवं कांच (गुदा) का क्षार सूत्र से, एवं आंतों की बीमारियों जैसे पेट का भारीपन, गैस, कब्ज, पुरुष और स्त्री के गुप्त रोगों का आयुर्वेदिक उपचार किया जाता है।

डॉ. के.एम. राव
एम.एस.(आयु) शल्य
भूतपूर्व प्राध्यापक शल्य विभाग
शासकीय आयुर्वेद कॉलेज अहमदाबाद

समय :- सोमवार से शनिवार, सुबह 10 से 2, शाम 6 से 7:30
रविवार सुबह 10 से 2, शाम को बंद रहेगा

बिलासपुर रोड, बिलासपुर चौक, अम्बिकापुर मो. 90099-56307

बारिश, भंडारण और सीमा, तीनों मोर्चों पर मुस्तैद प्रशासन

धान को भीगने से बचाने के पुख्ता इंतजाम, 24 चेकपोस्ट पर रात में भी पहरा

★ 54 उपार्जन केंद्रों में तिरपाल-कैप कवर के इंतजाम, 24 चेकपोस्ट पर एसडीएम खुद कर रहे रात्रि निगरानी
★ बारिश की आशंका पर प्रशासन अलर्ट, धान की सुरक्षा, भंडारण और सीमा निगरानी के लिए कार्ययोजना पर अमल
★ धान भीगने न पाए, बाहर से धान आने न पाए- बलरामपुर में प्रशासन की दोहरी मुस्तैदी

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बीच जिला प्रशासन तीन मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। पहला, बारिश से उपार्जित धान को सुरक्षित रखना। दूसरा, धान भण्डारण के लिए प्रबंधन। तीसरा, सीमावर्ती राज्यों से अवैध धान की आवक रोकना। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देश पर यह काम तय कार्ययोजना के तहत हो रहा है। राजस्व अमला, खाद्य और संबद्ध विभाग इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

बारिश की आशंका को देखते हुए जिले के सभी 54 उपार्जन केंद्रों में कैप कवर, पन्नी और तिरपाल की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। धंधापुर, बरतीकला और रामचन्द्रपुर सहित अन्य केंद्रों में यह व्यवस्था संबंधित अधिकारी सुनिश्चित कर रहे हैं। तेज हवा में कवर न उड़ें, इसलिए धान के सभी स्टैक रस्सियों से मजबूती से बाँधे जा रहे हैं। जमीन की नमी और बहते पानी से बचाव के लिए पर्याप्त डनेज रखने और फड़ के चारों ओर नालियों की सफाई कर जल निकासी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कहीं जलभराव न हो। कलेक्टर के निर्देश पर सभी केंद्र प्रभारी और समिति कर्मचारी 20 से 22 नवम्बर तक मुख्यालय में रहकर लगातार निगरानी रखेंगे। धान की स्टैकिंग और भौतिक सत्यापन के लिए भी कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। धान उपार्जन केंद्र के अलावा भी समीपस्थ स्थानों की चिन्हांकन कर धान भंडारण प्रबंधन को भी मजबूत किया जा रहा है। उपार्जन केंद्रों के पास अतिरिक्त भंडारण स्थल चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व अमला और खरीदी केंद्र प्रभारी मिलकर यह काम लगातार कर रहे हैं। सामरी और डीपाडीहकला में धान भंडारण के लिए अतिरिक्त भूमि चिन्हित की जा चुकी है। अन्य केंद्रों में भी धान भण्डारण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए उपार्जन केंद्र के पास के क्षेत्रों में वैकल्पिक स्थलों का चयन किया जा रहा है।



अन्य राज्यों से धान की अवैध आवक रोकने के लिए जिले में 24 चेकपोस्ट बनाए गए हैं, जहाँ तैनात अधिकारी रात्रि गश्त कर रहे हैं। सभी एसडीएम भी रात में चेकपोस्ट पर पहुँचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। रामानुजगंज विकासखंड में चुनापाधर, महादेवपुर, त्रिशुली (भेडरू बुटर), त्रिशुली (हल्दी मोड़), बालचउरा, हुरुपायर, अनिरुधपुर, रामानुजगंज, चंद्रनगर और नगरा बाबा में चेकपोस्ट हैं।

वाड्रफनगर विकासखंड में मुरकील, चपोता, केसाटी, गिरवानी और धनवार, कुसमी विकासखंड में कौरखा, पुदांग, अमटाही और करचा, तथा शंकरगढ़ विकासखंड में पौड़ीखुर्द, बादा और भुवनेश्वरपुर इत्यादि में चेकपोस्ट बनाए गए हैं।

कलेक्टर ने बरदर धान उपार्जन केन्द्र का किया औचक निरीक्षण, अतिरिक्त भंडारण के लिए वैकल्पिक स्थान पहले से चिह्नित करने के निर्देश

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवम्बर से शुरू हो चुकी है। खरीदी केन्द्रों पर किसानों की सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी लगातार औचक निरीक्षण कर रही हैं। इसी क्रम में उन्होंने आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, बरदर के धान उपार्जन केन्द्र का निरीक्षण किया। उन्होंने केन्द्र में किसानों के पंजीयन, बारदानों की उपलब्धता, धान की तौल और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कलेक्टर ने केन्द्र में धान रखने की निर्धारित क्षमता की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित राजस्व अधिकारी को निर्देश दिए कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त धान रखने के लिए वैकल्पिक स्थान पहले से चिह्नित कर लिया जाए। उन्होंने किसानों के बैठने, पेयजल और छाँव की व्यवस्था के साथ धान की गुणवत्ता जाँच और इलेक्ट्रॉनिक तौल की व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी शासन की प्राथमिकता वाला कार्य है। खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे और वास्तविक पंजीकृत किसानों से उनके पंजीकृत रकबे के अनुसार ही धान खरीदा जाए। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभाने के निर्देश दिए।

नवीन राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया के सरलीकरण की मांग

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। कांटारोली में गत दिनों आयोजित वोट बचाओ,देश बचाओ कार्यक्रम एवं जनचौपाल में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी एवं सांसद सुखदेव भगत, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव तथा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत को कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संदीप शर्मा ने पत्र सौंपकर नवीन राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में आ रही समस्याओं से अवगत कराया। शर्मा ने पत्र में उल्लेख किया है कि प्रदेश में नवीन राशन कार्ड बनाने के लिए परिवार के सदस्यों की जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र जैसी दस्तावेज के अनिवार्यता के कारण गरीब, किसान एवं मजदूर परिवारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर गरीब, अशिक्षित, बुजुर्ग, ग्रामीण एवं आर्थिक रूप सें कमजोर वर्ग के लोगों के लिए इन सभी दस्तावेजों की व्यवस्था करना कठिन है। ऐसे में आवश्यक दस्तावेजों की अनिवार्यता के चलते पात्र परिवारों को राशन कार्ड बनवाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत से आग्रह किया कि इस विषय को विधानसभा में शासन के समक्ष प्रमुखता से उठाते हुए नवीन राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण कराया जाए। साथ ही दस्तावेजों की अनिवार्यता में व्यवहारिक छूट प्रदान करने की दिशा में पहल की जाए, ताकि गरीब, किसान एवं मजदूर परिवारों को अनावश्यक परेशानी से राहत मिल सके और कोई भी पात्र परिवार राशन जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित न रहे।उन्होंने उम्मीद जताई कि इस जनहित से जुड़े विषय पर सकारात्मक पहल कर आम जनता की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।



ग्राम जोगबा में नि:शुल्क स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच शिविर का आयोजन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र की केतकी भूमिगत खदान द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व अंतर्गत शुक्रवार को ग्राम पंचायत जोगबा स्थित पंचायत भवन में नि:शुल्क स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया।



शिविर का संचालन केंद्रीय चिकित्सालय बिश्रामपुर एवं श्री रामकृष्ण आई हॉस्पिटल मनेन्द्रगढ़ के संयुक्त सहयोग से किया गया। शिविर में डॉ. हर्षवर्धन सिंह, डॉ. शुभांगी वर्मा, डॉ. सत्यपाल जोहले, डॉ. संदीप एवं उनकी टीम द्वारा ग्रामीणों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गईं। शिविर के दौरान ग्रामीणों का नेत्र परीक्षण एवं सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त मधुमेह की प्रारंभिक पहचान एवं उच्च रक्तचाप की जांच के उद्देश्य से लाभार्थियों की रक्त शर्करा एवं रक्तचाप की जांच भी की गई। जरूरतमंद लोगों को चिकित्सकीय परामर्श एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सुझाव प्रदान किए गए।शिविर में 70 ग्रामीण लाभार्थियों ने नि:शुल्क स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच की सुविधा का लाभ उठाया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं जरूरतमंद लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना, नेत्र एवं सामान्य रोगों की समय पर पहचान करना तथा मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। आयोजन में सब एरिया मैनेजर आरजीके प्रशांत शर्मा, केंद्रीय चिकित्सालय बिश्रामपुर के एएमओ यूएस बैठा, केतकी मैनेजर विनम्र जैन, सतीश वर्मा सहित केंद्रीय चिकित्सालय के चिकित्सक उपस्थित थे।

निर्वाचन साक्षरता क्लब की जिला स्तरीय निबंध एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता सम्पन्न, विजेताओं को मिले प्रमाण-पत्र

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार जिले के स्कूलों और महाविद्यालयों में गठित निर्वाचन साक्षरता क्लबों (ईएलसी) के अंतर्गत निबंध एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का जिला स्तरीय अंतिम चरण आज जिला ग्रंथालय, बलरामपुर में आयोजित हुआ। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देशन में 02 से 20 नवम्बर तक तीन चरणों में यह प्रतियोगिता निर्धारित की गई थी। निबंध का विषय 'शुद्ध मतदाता सूची का महत्व एवं मतदान का महत्व' था। प्रश्नोत्तरी मतदाता सूची तैयार करने, ईवीएम-वीवीपैट से मतदान और मतगणना प्रक्रिया पर आधारित थी।

पहले चरण में जिले के सभी शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल और महाविद्यालयों में प्रतियोगिताएँ हुईं। यहाँ से हर संस्था के दो-दो विद्यार्थी चुने गए, जिन्होंने विधानसभा स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिया। इसके बाद प्रतापपुर, रामानुजगंज और सामरी विधानसभा क्षेत्रों से निबंध एवं प्रश्नोत्तरी के लिए 10-10 विद्यार्थियों का चयन हुआ। इस तरह कुल 60 प्रतिभागी जिला स्तर पर पहुँचे। दोपहर 12 से 2 बजे तक चली अंतिम प्रतियोगिता के निबंध वर्ग में शासकीय महाविद्यालय रनहत की छात्रा मन्नु नेटी और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जामवन्तपुर की छात्रा राहतनाज प्रथम रहीं। प्रश्नोत्तरी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) रामानुजगंज की शर्मिला सिंह और सेजेस वाड्रफनगर के अनुराग गुप्ता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले विद्यार्थियों सहित सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र दिए गए।



ड्यूटी से वापस घर लौट रहे ठेका श्रमिक की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र के केतकी माइंस में कार्यरत ठेका श्रमिक की शुक्रवार की शाम बाइक से वापस घर लौटने के दौरान अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत डेडरी पनिकापारा निवासी करीब 35 वर्षीय ठेका श्रमिक दिनेश दास पिता खेम साय आज शाम बाइक में अपना ड्यूटी केतकी खदान से करके वापस घर लौट रहा था। तभी बिश्रामपुर-मानी मुख्य मार्ग पर ग्राम पंचायत डेडरी में अज्ञात वाहन की टक्कर से ठेका श्रमिक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच शव को उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिश्रामपुर के मर्चुरी में लाकर रखवा दिया है। शनिवार को पीएम उपरांत मामले की जांच शुरू की जाएगी।



15 सूत्रीय मांगों को लेकर क्रमिक भूख चौथे दिन भी जारी

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। संयुक्त कोयला मजदूर संघ एटक बिश्रामपुर क्षेत्र द्वारा ठेका श्रमिकों की 15 सूत्रीय लंबित मांगों के निराकरण की मांग को लेकर 17 नवंबर से महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष जारी सात दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल आज चौथे दिन भी जारी रही। भूख हड़ताल पर आज चौथे दिन ठेका श्रमिक क्रमश: बिजेन्द्र कुमार, अंकित राजवाड़े, शिवनारायण सिंह, यमुना प्रसाद, अमर सिंह, दीगर सिंह, फुलेश्वर प्रसाद, रामविलास, दुलार सिंह, यमराज विश्वकर्मा बैठे रहे। संघ के क्षेत्रीय सचिव पंकज कुमार गर्ग ने बताया कि यदि निर्धारित अवधि में भी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो 25 नवंबर से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। ठेका श्रमिकों की मांग है कि कोयला ट्रांसपोर्ट, साइडिंग, सोलर प्लांट एवं खान परिसर के सभी कामगारों को एचपीसी वेज का भुगतान हो।



सभी खदानों में कार्य समिति का अनिवार्य गठन किया जाए। सभी ठेका श्रमिकों को नियमानुसार नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र प्रदान किया जाए। बायोमेट्रिक व उपस्थिति रजिस्टर में हाजिरी दर्ज हो एवं प्रति माह 26 दिन का कार्य सुनिश्चित किया जाए। हर महीने की 7 तारीख तक वेतन भुगतान और अनिवार्य वेतन पर्ची दी जाए। कॉरपोरेट बैंक खातों से वेतन भुगतान हो ताकि श्रमिकों को कॉरपोरेट बीमा का लाभ मिल सके। बोनस/पीएलआई का पूर्ण भुगतान हो तथा गायत्री एवं केतकी खदान के वर्ष 2024-25 का बकाया बोनस तुरंत दिया जाए। खदानों में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन हो और दुर्घटनाओं को छुपाने की प्रथा पर तत्काल रोक लगे। गायत्री एवं केतकी खदान के आसपास रोजगार के नाम पर हो रही अवैध धन उगाही की उच्चस्तरीय जांच कराकर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। पूर्व में वेतन से काटी गई सीएमपीएफ राशि की तत्काल वापसी या समायोजन किया जाए।

स्वामित्व योजना में बलरामपुर-रामानुजगंज जिला प्रदेश में प्रथम, सभी 801 अधिकार अभिलेख वितरित

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले ने लक्ष्य के विरुद्ध शत-प्रतिशत प्रगति हासिल की है और प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जिले के 160 ग्रामों में 801 अधिकार अभिलेख तैयार कर सभी हितग्राहियों को वितरित कर दिए गए हैं।

अधीक्षक भू-अभिलेख की 18 नवम्बर की रिपोर्ट के अनुसार योजना के तहत जिले के 188 ग्रामों में ड्रोन सर्वे पूरा किया गया। सर्वे ऑफ इंडिया से 179 ग्रामों के मैप-1 प्राप्त हुए। इन सभी का भौतिक सत्यापन करके उन्हें वापस भेज दिया गया है और अब जिले के पास कोई भी मैप-1 लंबित नहीं है। इसके बाद 160 ग्रामों के मैप-2/मैप-3 प्राप्त हुए। इन सभी ग्रामों का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। अंतिम प्रकाशन के आधार पर 801 अधिकार अभिलेख तैयार कर उनका डाटा ऑनलाइन अपलोड किया गया। सभी 801 अभिलेख हस्ताक्षरित होकर हितग्राहियों तक पहुँच चुके हैं, इसलिए वितरण के लिए कोई अभिलेख शेष नहीं है।

कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने इस उपलब्धि के लिए राजस्व विभाग और योजना से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाली महत्वपूर्ण योजना है। इससे ग्रामीणों को अपने घर पर अधिकार का दस्तावेजी प्रमाण मिला है, जिससे वे बैंक ऋण जैसी सुविधाओं का लाभ आसानी से ले सकेंगे। इसके साथ ही स्वरोजगार व व्यवसाय के लिए आसानी से ऋण प्राप्त कर आर्थिक रूप से संबल प्राप्त कर सकते हैं। स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को अपने मकान और आबादी भूमि का कानूनी स्वामित्व प्रमाण-पत्र मिलता है। संपत्ति कार्ड के आधार पर बैंक से ऋण लेना आसान होता है। संपत्ति का मूल्य बढ़ता है और उत्तराधिकार व संपत्ति के लेन-देन में स्पष्टता आती है। ग्राम पंचायतों को आबादी भूमि का व्यवस्थित अभिलेख और जीआईएस आधारित डिजिटल मानचित्र मिलता है। इनकी मदद से शासकीय भूमि की पहचान, अतिक्रमण पर नियंत्रण और ग्राम विकास की बेहतर योजना बनाना संभव होता है।

राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ने के साथ यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत बनाने में सहायक है।

जइया मिर्च के संरक्षण के लिए रामलाल लहरे को राष्ट्रीय सम्मान, कलेक्टर ने दी शुभकामनाएँ

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने आज कलेक्टर कक्ष में प्रगतिशील कृषक श्री रामलाल लहरे से मुलाकात कर उन्हें 'प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर रिकॉग्निशन' राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर हार्दिक शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने श्री लहरे से कहा कि वे आगे भी पारंपरिक, देशी और जंगली पौधों की आनुवंशिक विविधता के संरक्षण और संवर्धन में बेहतर कार्य करें तथा क्षेत्र के अन्य किसानों को भी इसके लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक तथा उप संचालक कृषि श्री अनिल वर्मा ने भी श्री रामलाल लहरे को शुभकामनाएँ दीं। वाड्रफनगर विकासखंड के ग्राम महुली निवासी श्री लहरे को यह सम्मान छत्तीसगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली दुर्लभ जंगली जइया मिर्च के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिला है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने उन्हें यह सम्मान 12 नवम्बर को दिया।



प्राधिकरण के 22वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर (एनएएससी), पूसा, नई दिल्ली में समारोह आयोजित हुआ। इसके मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. प्रमोद कुमार मिश्र थे। सम्मान में प्रमाण-पत्र, स्मृति चिन्ह और एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई।

यह राष्ट्रीय सम्मान उन किसानों को दिया जाता है जो पौधों की नई किस्में विकसित करते हैं या पारंपरिक बीजों का संरक्षण और संवर्धन करते हैं। श्री लहरे की विकसित 'जइया-1' मिर्च किस्म पौधा किस्म रजिस्ट्री में कृषक किस्म के रूप में पंजीकृत है। बायोटेक्नोलॉजी में स्नातकोत्तर श्री लहरे को इससे पहले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पूसा से 'नेशनल इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2020' भी मिल चुका है।

शब्दबीज की समीक्षा में कलेक्टर ने शिक्षकों के प्रयासों को सराहा, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रामानुजनगर। जिले में संचालित अभिनव शैक्षिक पहल शब्दबीज के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा के लिए कलेक्टर रेना जमील ने जिला एवं विकासखंड नोडल की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा मनोज कुमार साहू ने कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति, अब तक हुई प्रगति तथा विद्यालय स्तर पर इसके क्रियान्वयन की जानकारी प्रस्तुत की।कलेक्टर रेना जमील ने अल्प अवधि में शब्दबीज कार्यक्रम के माध्यम से जिले में हुई प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसके



सफल क्रियान्वयन में योगदान देने वाले समस्त शिक्षकों एवं संबंधित नोडलों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि शब्दबीज केवल शब्दों के अभ्यास तक सीमित कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में भाषा संबंधी बुनियादी दक्षताओं का विकास करना, उनकी शब्द संपदा बढ़ाना तथा सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की क्षमता को मजबूत बनाना है। इसलिए कार्यक्रम को प्रत्येक विद्यालय में पूरी गंभीरता, नियमितता एवं प्रभावशीलता के साथ संचालित किया जाना आवश्यक है।

लापरवाही पर समझाइश के बाद होगी सख्त कार्रवाई

समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों एवं सुधार की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए जिला एवं विकासखंड नोडल को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभी संस्था प्रमुखों एवं शिक्षकों की सक्रिय सहभागिता अनिवार्य है।जिन विद्यालयों में कार्यक्रम के संचालन में लापरवाही अथवा उदासीनता पाई जाएगी, वहां संबंधित संस्था प्रमुखों एवं शिक्षकों को पहले समझाइश देकर सुधार का अवसर दिया जाए।इसके बावजूद अपेक्षित सुधार नहीं होने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बेहतर परिणामों के लिए समन्वय और नियमित मॉनिटरिंग पर जोर

कलेक्टर ने कार्यक्रम की नियमित मॉनिटरिंग, विद्यालय स्तर पर गतिविधियों के प्रभावी संचालन तथा सभी स्तरों पर बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष जोर दिया।उन्होंने कहा कि शब्दबीज की सफलता तभी सुनिश्चित होगी, जब प्रत्येक शिक्षक इसे अपनी नियमित शैक्षणिक जिम्मेदारी का हिस्सा बनाकर बच्चों के साथ निरंतर अभ्यास कराएगा। उन्होंने जिला एवं विकासखंड नोडलों को मैदानी स्तर पर कार्यक्रम की प्रगति पर सतत निगरानी रखने तथा आवश्यकतानुसार विद्यालयों को मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए।उन्होंने सभी अधिकारियों, संस्था प्रमुखों एवं शिक्षकों से सामूहिक जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए शब्दबीज को जिले की एक प्रभावी शैक्षिक पहचान बनाने की अपेक्षा व्यक्त की। समीक्षा बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विजेंद्र कुमार पाटले, डिप्टी कलेक्टर यशवंत देवांगन, जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा मनोज कुमार साहू, शब्दबीज के जिला नोडल गौतम कुमार शर्मा, सहायक जिला नोडल विजय बरगाह, कुमारी टेसु सुमन एवं बुधराम साहू सहित विकासखंड नोडल रामानुजनगर राधेश्याम साहू, प्रेमनगर पुष्पराज पाण्डेय, ओड़गी दिनेश कुमार पाण्डेय, भैयाथान जुगेन्द्र सोनी, प्रतापपुर शैलेश जायसवाल और शिक्षक दीपेश यादव उपस्थित रहे।

भाजपा नेता पर 50 लाख वसूली का आरोप, सड़क निर्माण में लगे कर्मचारियों से मारपीट का आरोप

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

राजनांदगांव। भाजपा नेता भरत वर्मा पर सड़क निर्माण में लगे ठेकेदार के कर्मचारियों से अभद्रता और 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगा है।ठेकेदार के कर्मचारियों ने भरत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। राजनांदगांव से मोहला-मानपुर तक लोक निर्माण विभाग द्वारा करोड़ों रुपये की लागत से सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। यह काम कन्हैयालाल अग्रवाल कंपनी को ठेके में मिला है।कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर मनीष कुमार साहू ने बताया कि ग्राम कुमारदा



एवं घुसपाल के मध्य निर्माण कार्य के दौरान भरत वर्मा द्वारा कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज एवं मारपीट की गई। प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि पूर्व में भी भरत वर्मा ने कार्य के संबंध में गाली-गलौज और मारने-पीटने की धमकी दी थी। साथ ही कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नवीन अग्रवाल से 50 लाख रुपये वसूली की मांग भी की है। इसी वसूली की राशि नहीं देने पर कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई।उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा किए जा रहे कार्य का विभाग एवं उच्च अधिकारियों द्वारा निरंतर निरीक्षण कर गुणवत्ता की जांच की जा रही है। जांच में सही पाए जाने के पश्चात ही कार्य किया जा रहा है, किंतु भरत वर्मा द्वारा बार-बार कार्य को लेकर ब्लैकमेलिंग की जा रही है। कर्मचारियों को जान से मारने-पीटने की धमकी लगातार दी जा रही है। भरत वर्मा द्वारा लगातार किए जा रहे दुर्व्यवहार से कर्मचारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।बिना सुरक्षा के कार्य किया जाना संभव नहीं है। इसलिए कंपनी द्वारा खैरागढ़ से राजनांदगांव और राजनांदगांव से मानपुर का काम बंद किया जा रहा है।

एसएसपीयू के स्नेहा सिंह एवं रुद्रतिया सिंह ने राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता में जीते कांस्य पदक

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भिलाई के विद्यार्थियों ने खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ (उत्तर प्रदेश) में आयोजित ऑल इंडिया इंटर-यूनिवर्सिटी आर्म रेसलिंग टूनार्मेंट 2026 में विश्वविद्यालय के दो विद्यार्थियों ने कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। प्रतियोगिता में डीसीए प्रथम सेमेस्टर की छात्रा सुश्री स्नेहा सिंह ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त किया। वहीं, बीबीए



प्रथम सेमेस्टर के छात्र रुद्रतिया सिंह ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर विश्वविद्यालय को गौरवान्वित किया। दोनों विद्यार्थियों ने यह उपलब्धि खेल अधिकारी युवराज राउत के मार्गदर्शन में हासिल की। दोनों विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री आई.पी. मिश्रा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि स्नेहा सिंह एवं रुद्रतिया सिंह की यह उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और खेल भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है। हमें गर्व है कि हमारे विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ा रहे हैं। दोनों विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। कुलपति डॉ. स्मिता सेलट, कुलसचिव डॉ. वैभव तिवारी एवं डायरेक्टर डेवलपमेंट डॉ. सुशील चंद्र तिवारी ने भी विद्यार्थियों की सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यह उपलब्धि उनकी मेहनत, अनुशासन, लगन और खेल के प्रति समर्पण का परिणाम है। उनकी सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणास्रोत है। विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ खेल एवं अन्य सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करता है।

धान खरीदी और आदान सहायता से किसानों को मिलेगा आर्थिक संबल, किसान ने जताया सीएम का आभार

अम्बिकापुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में शासन द्वारा ?3,100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी और ?13,839 प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता दी जा रही है। रामपुर केंद्र में धान बेचने पहुंचे ग्राम नवाबांध के किसान अर्जुन राम राजवाड़े ने इस व्यवस्था की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। राजवाड़े ने कहा कि पहले बिचौलिए अंतर की राशि को लेकर किसानों को बहला-फुसलाकर कम पैसे देकर शोषण करते थे। अब 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचने वाले किसानों को भी कृषक उन्नति योजना के तहत पूरी आदान सहायता मिलेगी, यह सराहनीय कदम है।

फास्टैग से खुला गांजा तस्करी का राज, 70 किलो गांजा के साथ फरार आरोपी गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

बसंतपुर। पुलिस ने 70 किलो 390 ग्राम गांजा तस्करी के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सितंबर में ग्राम फुलीडुमर से महुवारी जाने वाले रास्ते पर लावारिस खड़ी इनोवा कार से 34 पैकेट गांजा जब्त किया था। गांजे की कीमत 35 लाख 19 हजार 500 रुपये और कार की कीमत करीब 15 लाख रुपये आंकी गई थी। पुलिस के मुताबिक, 22 सितंबर 2026 को थाना प्रभारी को सूचना मिली कि ग्राम फुलीडुमर के महुवारी मार्ग के किनारे एक इनोवा कार काफी समय से लावारिस खड़ी है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो महाराष्ट्र नंबर की कार (एमएच 04 डीवाई



9471) मिली। कार लॉक थी, इसलिए मैकेनिक से उसका दरवाजा खुलवाया गया। गवाहों की मौजूदगी में तलाशी लेने पर डिक्की से भूरे टेप में लिपटे 18 पैकेट और हरी प्लास्टिक की बोरी में रखे 16 पैकेट मिले। जांच में सभी पैकेटों में गांजा मिला। कुल 70.390 किलो गांजा जब्त कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(ई)(सी) के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के दौरान कार में लगे फास्टैग और अन्य तकनीकी जानकारी के आधार पर आरोपी की पहचान की। महाराष्ट्र के पालघर के अशोक कुमार यादव (43) को हिरासत में लिया गया। आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मिजार्पुर का रहने वाला है। पूछताछ में अशोक ने बताया कि जुलाई 2026 में वह एक साथी के साथ ओडिशा के सुंदरगढ़ गया था। वहां इनोवा में गांजा लोड किया गया। 22 सितंबर को वह गांजा लेकर उत्तर प्रदेश जा रहा था। उसने बताया कि वाड्रफनगर के आसपास एक ट्रक के हादसे के कारण आगे चल रही कार ने अचानक ब्रेक लगाया। उसकी इनोवा कार पीछे से टकरा गई। पुलिस कार्रवाई के डर से वह कार को कच्चे रास्ते पर खड़ी कर साथियों के साथ फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर अदालत में पेश किया है। मामले में अन्य आरोपियों और गांजा तस्करी के नेटवर्क की जांच जारी है।

जनगणना के निदेशों के बीच तहसीलदार का तबादला, मनहरण राठिया को मिली कमान

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

भटगांव। कलेक्टर सूरजपुर के 18 नवंबर के आदेश से भटगांव तहसीलदार बदल गए हैं। शिवनारायण राठिया को रामानुजनगर भेजा गया है, जबकि रामानुजनगर के तहसीलदार मनहरण राठिया को भटगांव की जिम्मेदारी मिली है। आदेश तत्काल प्रभावशील है।

जनगणना कार्य पूरा होने तक स्थानांतरण नहीं करने के निर्देश

जनगणना निदेशालय ने 29 अक्टूबर को और सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 नवंबर को पत्र जारी कर जनगणना 2027 के द्वितीय चरण में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों का 6 माह या कार्य पूर्ण होने तक यथासंभव तबादला नहीं करने के निर्देश दिए थे।

मई में पहला चरण पूरा, अब दूसरे चरण की तैयारी

जनगणना का प्रथम चरण 1 से 30 मई 2026 के बीच पूरा हो चुका है। द्वितीय चरण की तैयारी में अक्टूबर से जिला व संभाग स्तर पर प्रशिक्षण शुरू है। नवंबर में मास्टर ट्रेनर्स और दिसंबर से फील्ड ट्रेनर्स का प्रशिक्षण निर्धारित है।



भटगांव के तबादले पर अब प्रशासन के जवाब का इंतजार

सवाल है कि क्या शिवनारायण राठिया जनगणना कार्य में संलग्न थे? यदि थे तो किस आधार पर तबादला हुआ? आदेश में जनगणना ड्यूटी का उल्लेख नहीं है, इसलिए प्रशासन के आधिकारिक पक्ष का इंतजार है।

आत्मानंद स्कूल में वसूली का आरोप, कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

बेमेतरा। जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में संविदा शिक्षकों ने प्राचार्य और एक शिक्षक के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। शिक्षकों का आरोप है कि उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है और गोपनीय चरित्रावली खराब करने की धमकी देकर 10 हजार रुपये मांगे जा रहे हैं। शिकायत के अनुसार, विद्यालय के प्राचार्य गेंदलाल चतुर्वेदी और शिक्षक भारत लाल कश्यप के खिलाफ संविदा शिक्षकों ने शिकायत की है। आरोप है कि प्राचार्य के नाम पर शिक्षक भारत लाल कश्यप संविदा शिक्षकों से 10 हजार रुपये की मांग कर रहे हैं। पैसे नहीं देने पर सीआर



खराब करने और भविष्य में नौकरी से हटवाने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायत में महिला कर्मचारियों के साथ मानसिक प्रताड़ना और मातृत्व अवकाश के बदले पैसे मांगने जैसी गंभीर बातें भी सामने आई हैं। संविदा शिक्षकों का कहना है कि लगातार दबाव और धमकियों के कारण स्कूल में भय का माहौल बना हुआ है, जिससे शिक्षकों के कामकाज और पढ़ाई का वातावरण प्रभावित हो रहा है। शिक्षकों ने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, कथित अवैध वसूली और प्रताड़ना पर कार्रवाई करने के साथ नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बेमेतरा कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने जिला शिक्षा अधिकारी को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने बिलासपुर कलेक्टर और निगम आयुक्त को जारी किया अवमानना नोटिस

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

बिलासपुर। शहर के व्यस्ततम इलाके पुराना बस स्टैंड स्थित निराला नगर में 80 फीट चौड़ी मुख्य सड़क की शासकीय जमीन पर हुए कथित अतिक्रमण और अवैध निर्माण को नहीं हटाने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश का पालन नहीं होने पर बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल और नगर निगम आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी किया है। जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच ने प्रतिवादियों को तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि आदेश



की अवहेलना पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। बिलासपुर निवासी श्याम कश्यप ने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के माध्यम से यह अवमानना याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जय कुमार देवांगन ने पक्ष रखा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुराना बस स्टैंड के पास निराला नगर में राजा होटल के सामने सीरीश पांडेय, गिरीश पांडेय और आशीष पांडेय द्वारा शासकीय सड़क की जमीन पर कब्जा कर अवैध दुकानें और दो मंजिला व्यावसायिक परिसर बना लिया गया है। निर्माण के लिए न तो नगर निगम से नक्शा पास कराया गया और न ही कोई वैध अनुमति ली गई। जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज भी नहीं होने का दावा किया गया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि अग्रसेन चौक से श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुराना बस स्टैंड चौक तक सड़क की वास्तविक चौड़ाई 80 फीट है। लेकिन, इस अवैध कब्जे के कारण मुख्य मार्ग संकरा हो गया है। इससे इलाके में आए दिन यातायात बाधित हो रहा है और जाम लगने के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। मामले में याचिकाकर्ता ने करीब दो साल तक कलेक्टर, निगम आयुक्त और भवन अधिकारी से शिकायत की थी। आरोप है कि नगर निगम ने निर्माण को अवैध मानते हुए अतिक्रमण हटाने का नोटिस तो जारी किया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसके बाद दायर याचिका पर 30 जून 2026 को जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की पीठ ने नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव, कलेक्टर और निगम आयुक्त को जांच कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर अब अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रशासनिक अमले को तलब किया है।

चिंतन

अंतरविरोधों के बीच कैसे बनेगी सहमति



कॉप-31

प्रमोद भार्गव

वैश्विक राजनीति में तीन महाशक्तियों के शीर्ष नेताओं का एक मंच पर आना अपने आप में महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या गहरे मतभेदों और परस्पर विरोधी हितों के बीच कोई सहमति बन पाएगी? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की चीन के शेनझेन में होने वाली त्रिपक्षीय बैठक पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। तीनों नेता एपेक समिट के स्वागत डिनर में एक साथ नजर आए। यह तस्वीर कूटनीतिक लिहाज से भले ही आकर्षक हो, लेकिन इसके पीछे मौजूद अंतरविरोधों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ईरान युद्ध, परमाणु हथियारों का खतरा, वैश्विक व्यापार, टैरिफ, तेल और सामरिक वर्चस्व जैसे मुद्दों पर तीनों देशों के हित एक-दूसरे से टकराते रहे हैं। ऐसे में बैठक की सफलता केवल आपसी गर्मजोशी से नहीं, बल्कि ठोस सहमति बनाने की क्षमता से तय होगी। इस मुलाकात के कूटनीतिक महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग प्रोटोकॉल तोड़कर ट्रम्प का स्वागत करने खुद एयरपोर्ट पहुंचे। जिनपिंग का यह कदम महज औपचारिकता नहीं, बल्कि अमेरिका के साथ रिश्तों को महत्व देने का राजनीतिक संदेश भी है। इससे पहले सितंबर में अमेरिका यात्रा के दौरान ट्रम्प भी जिनपिंग के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। यानी दोनों देश कूटनीतिक शिष्टाचार के जरिए रिश्तों में गर्मजोशी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, तकनीक पर नियंत्रण, ताइवान और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रभाव को लेकर गहरे मतभेद हैं। दूसरी ओर, रूस और अमेरिका के संबंध यूक्रेन युद्ध और प्रतिबंधों के कारण तनावपूर्ण रहे हैं। चीन और रूस की नजदीकी भी अमेरिकी रणनीतिक चिंताओं का विषय है। ऐसे में तीनों देशों के लिए एक साझा एजेंडे पर सहमत होना आसान नहीं होगा। ईरान युद्ध और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका ने इन चुनौतियों को और गंभीर बना दिया है। यदि दुनिया की तीन बड़ी ताकतें इन मुद्दों पर जिम्मेदार भूमिका निभाती हैं तो तनाव कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हो सकती है। इस बैठक के लिए शेनझेन का चयन भी प्रतीकात्मक महत्व रखता है। कभी मछुआरों का छोटा-सा गांव रहा यह शहर चीन के आर्थिक और तकनीकी सामर्थ्य का बड़ा केंद्र बन चुका है। जिनपिंग ने भी शेनझेन को चीन के पांच दशक के विकास का प्रतीक बताते हुए दुनिया को यहां आने का संदेश दिया। तीनों देशों के बीच सहमति बनने का असर केवल उनके आपसी संबंधों तक सीमित नहीं रहेगा। वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति, निवेश और सुरक्षा व्यवस्था भी इससे प्रभावित होगी। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए भी इन समीकरणों का विशेष महत्व है। दुनिया पहले ही युद्धों, आर्थिक अनिश्चितता और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव से जूझ रही है। ऐसे में महाशक्तियों के बीच टकराव का खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। बहरहाल, कूटनीति में मुलाकातें संभावनाओं के दरवाजे खोलती हैं, लेकिन समाधान की गारंटी नहीं होती। ट्रम्प, पुतिन और जिनपिंग को समझना होगा कि शक्ति प्रदर्शन और एक-दूसरे को दबाने की रणनीति से स्थायी शांति संभव नहीं है। हाथ मिलाने और साथ बैठकर भोजन करने की तस्वीरें तभी सार्थक होंगी, जब बातचीत मतभेद कम करने और साझा समाधान तलाशने तक पहुंचेगी। असली चुनौती यही है कि अंतरविरोधों के बीच सहमति का रास्ता कैसे निकले।

> दुनिया की निगाहें तुर्किये के अंताल्या नगर में चल रहे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, यानी कॉप-31 पर टिकी हैं। इसका मुख्य लक्ष्य पुराने जलवायु सम्मेलन के वादों को धरातल पर उतारना है। भारत जलवायु न्याय और विकासशील देशों के लिए वित्तीय मदद की पुरजोर पैरवी कर रहा है। करीब 200 देशों के इस सम्मेलन में अमेरिका आधिकारिक रूप से अनुपस्थित है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने लगातार दूसरी बार इस सम्मेलन में कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा है। पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका के हटने के बाद से व्हाइट हाउस ने इन वार्ताओं से दूरी बना ली है, जिससे वह विकासशील देशों को किसी भी प्रकार की आर्थिक एवं तकनीकी मदद से बचा रहे।

वादे पूरे होने पर थमेगी तापमान में वृद्धि

धरती के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। बढ़ते तापमान के दुष्परिणाम धरती पर खुले रूप में दिखाई दे रहे हैं। कहीं भीषण गर्मी तो कहीं खून जमा देने वाली ठंड आबादी को प्रभावित कर रही है। साथ ही, बाढ़, सूखा, चक्रवात, टूटते हिमनद, समुद्र का बढ़ता जलस्तर, वनों में आग और कम अवधि में आते भूकंप निरंतर प्रकृति के संतुलन को चुनौती देते हुए जनजीवन को झकझोर रहे हैं। कुछ माह पहले नेपाल और तिब्बत में हिमखंड टूटने से ही लोगों को भीषण जल आपदा का सामना करना पड़ा था। केदारनाथ आपदा भी हिमखंड टूटने का परिणाम थी। प्रकृति के ये संकेत बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन अब केवल पर्यावरण विज्ञानियों की चिंता का विषय नहीं रह गया है, अपितु यह मानव सभ्यता, आवास, रोजगार और खाद्य सुरक्षा के साथ विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को भी चुनौती दे रहा है। इन सवालों के साथ दुनिया की निगाहें तुर्किये के अंताल्या नगर में चल रहे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, यानी कॉप-31 पर टिकी हैं। इसका मुख्य लक्ष्य पुराने जलवायु सम्मेलन के वादों को धरातल पर उतारना है। भारत जलवायु न्याय और विकासशील देशों के लिए वित्तीय मदद की पुरजोर पैरवी कर रहा है।

करीब 200 देशों के इस सम्मेलन में अमेरिका आधिकारिक रूप से अनुपस्थित है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने लगातार दूसरी बार इस सम्मेलन में कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा है। पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका के हटने के बाद से व्हाइट हाउस ने इन वार्ताओं से दूरी बना ली है, जिससे वह विकासशील देशों को किसी भी प्रकार की आर्थिक एवं तकनीकी मदद से बचा रहे। ऐसे में यहां बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि ग्रीनहाउस दुष्प्रभावों से लड़ने के लिए धन कहां से मिलेगा? हालांकि तुर्की मेजबान और अध्यक्षता के रूप में कार्य योजना का दायित्व संभाल रहा है और ऑस्ट्रेलिया वार्ता के साथ समझौते का प्रारूप तैयार करेगा। विकासशील देशों के लिए 2035 तक सालाना 300 अरब डॉलर जलवायु वित्त जुटाने का लक्ष्य रखा है। पेरिस समझौते से अमेरिका के हटने के बाद पैदा हुए आर्थिक अंतर की पूर्ति के लिए अन्य विकसित देशों पर भी दबाव बनाया जा रहा है। इस बार मुख्य एजेंडे में स्वच्छ ऊर्जा और विद्युतिकरण के जरिए वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेलिस्यस तक लाना है। इस हेतु जीवाष्म ईंधन (कोयला, तेल और गैस) पर निर्भरता घटाने और परिवहन व उद्योगों में विद्युतिकरण बढ़ाने पर सहमति बनाई जा रही है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव बातचीत में प्रयास कर रहे हैं कि आर्थिक एवं तकनीकी रूप में समृद्ध संपन्न पश्चिमी यूरोप सम्मेलन में हुए वादों को पूरा करने की संयुक्त जिम्मेदारी उठाए। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा की सस्ती एवं प्रभावी तकनीकें विकासशील देशों को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की शर्तों का पालन किए बिना मुफ्त में दे। इस ऊर्जा के भंडारण के उपायों से जुड़ी तकनीकें भी दें। जलवायु लक्ष्यों को साधना है तो ऐसा जरूरी है, क्योंकि भारत जैसे विकासशील देश ने सौर एवं पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता 164 गीगावाट करके बड़ी छलांग तो लगाई है, लेकिन भंडारण तकनीक के अभाव में 17-18 प्रतिषत ऊर्जा ही उपयोग में आ रही है।



ऐसे में भारत को कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन भी बड़ी मात्रा में करना पड़ रहा है। साफ है, अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए भारत जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा उत्पादन को पूरी तरह बंद नहीं कर सकता है।

अतएव भारत जैसे देशों को धन और प्रौद्योगिकी दोनों की जरूरत है? वैसे भी इस सम्मेलन में भारत और जर्मनी के पास 2035 तक स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सम्मेलन में भागीदार देशों के बीच आम सहमति बनाए जाने की जिम्मेदारी है, जिससे तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक लाया जा सके। नवीनतम तकनीक से दक्ष निगरानी संचार उपग्रह ही मौसम के पूर्वानुमान, लगाकर प्राकृतिक आपदा किस भू-क्षेत्र में संभावित है, इसकी सूचना एवं भयावहता की चेतावनी दे सकते हैं। कृत्रिम बुद्धि आधारित ये संचार सूचनाएं यदि आपदा पूर्व मिल जाती हैं तो अत्यधिक बारिश, समुद्री चक्रवात, सौर तूफान और भू-गर्भीय हलचलों के परिणाम से निकले विस्फोटक भूकंपों से न केवल मानव आबादी बची रहेगी, बल्कि मानवों को सुरक्षित रखने वाले संसाधन भी सुरक्षित रहेंगे। अतएव कार्बन को अवशोषित, ग्रीन हाइड्रोजन, उन्नत इलेक्ट्रिक बैटरी और स्वच्छ ऊर्जा हासिल करने की दक्षता से जुड़ी तकनीकें विकासशील देशों को निशुल्क देने की सुविधा पर आम सहमति बनती है तो दूषित कार्बन उत्सर्जन में कमी लाकर पृथ्वी के बढ़ते तापमान को 1.5 डिग्री पर लाने के लक्ष्य को साधने की उम्मीद बढ़ जाएगी? जीवाश्म ईंधन के परिप्रेक्ष्य में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन पर आरोप लगाया था कि इन दोनों देशों ने विकसित देशों से अरबों डॉलर की मदद लेने की शर्त पर समझौते पर दस्तखत किए हैं।

लिहाजा यह समझौता अमेरिका के आर्थिक हितों को प्रभावित करने वाला है। यही नहीं, ट्रंप ने आगे कहा था कि भारत ने 2020 तक अपना कोयला उत्पादन दोगुना करने की अनुमति भी ले ली है। वहीं चीन ने कोयले से चलने वाले सैकड़ों बिजलीघर चालू करने की शर्त पर दस्तखत किए हैं। साफ है यह समझौता अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाने वाला है। ट्रंप ने यहां तक कहा था कि संयुक्त राष्ट्र की 'हरित जलवायु निधि अमेरिका से धन हथियाने की साजिश है। तभी ट्रंप की इस सोच ने तय कर दिया था कि अमेरिका अब वैश्विक समस्याओं के प्रति उदार रुख नहीं अपनाएगा। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को करारा जवाब देते हुए कहा था कि 'भारत प्राचीनकाल से ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाता चला आ रहा है। हमारे 5000 साल पुराने शास्त्र पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग रहे हैं। हम 40 करोड़ एलईडी बल्ब घर-घर पहुंचाकर हजारों मेगावाट बिजली बचाकर कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने में लगे हैं।' यहां यह स्पष्ट करना मुनासिब होगा कि पेरिस समझौते के बाद 2015 में भारत को हरित जलवायु निधि से कुल 19000 करोड़ रुपये की मदद मिली थी।

इसमें अमेरिका का हिस्सा महज 600 करोड़ रुपये था। ऐसे में ट्रंप का यह दावा नितांत खोखला था कि भारत को इस निधि से अमेरिका के जरिए बड़ी मदद मिल रही है। साफ है कि ट्रंप के इस पर्यावरण संरक्षण विरोधी मानसिकता के जवाब में ही वित्तीय अंतर को भरने के लिए इस सम्मेलन में विकासशील देश अन्य विकसित देशों से धन एवं तकनीक की मदद दिए जाने की उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि जलवायु परिवर्तन के लिए दोषी तो औद्योगिक और प्रौद्योगिकी उत्पादन करने वाले अमेरिका जैसे विकसित देश हैं, किंतु इसका नुकसान बढ़ते तापमान के चलते नेपाल जैसे छोटे देश उठाने को मजबूर हो रहे हैं। इसीलिए नेपाल में जब बाढ़ के रूप में भीषण प्राकृतिक आपदा आई थी, तब नेपाल ने इस जलवायु आपदा में हुए नुकसान की पूर्ति की मांग भी विकसित देशों से की थी।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

मंथन

डॉ. मोनिका शर्मा



मृत्युदंड की सजा - स्पष्ट

दृष्टिकोण भारत का अधिकार

भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में किसी बर्बर अपराध को अंजाम देने वाला अपराधी बच निकलने के बाद फिर अपराध करने से नहीं चूकता। हमारे देश में तो ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। सामूहिक बलात्कार, निर्मम हत्या, आतंकी गतिविधियों तक में यह लिप्तता देखने को मिली है। यही वजह है कि समाज का बड़ा एक वर्ग जघन्य और अत्यंत क्रूर अपराधों में कठोरतम सजा देने को सही ठहराता है। कठोर दंड को सामाजिक परिवेश में न्याय की भावना और अपराधियों में भय पैदा करने के लिए आवश्यक मानता है। विशेषकर निर्मम अपराधों के मामलों में पीड़ित परिवार यह महसूस करते हैं कि जीवनभर की सजा पर्याप्त बजाय मृत्युदंड मिलना ही सही न्याय है। हाल में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हमारे देश का मृत्युदंड पर रोक लगाने से जुड़े मसौदा प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान करना बर्बर मानसिकता के प्रति स्पष्ट रुख रखने की बानगी बना। समाज-परिवार और देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में अपनी संप्रभु सोच को स्पष्ट किया। असल में इस प्रस्ताव में मृत्युदंड दिए जाने पर चिंता जताते हुए कहा गया था कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप अपनी न्याय व्यवस्था विकसित करने और उचित कानूनी दंड तय करने का अधिकार सभी देशों को है। ऐसे में हमारे देश ने गंभीरतम अपराधों के लिए मृत्युदंड का विकल्प बनाए रखने का निर्णय लिया है। यह पहली बार नहीं है जब भारत ने इस मोर्चे पर अपनी बात स्पष्टता से रखी है। वर्ष 2016, 2018 और 2024 में भी दुनियाभर में फांसी की सजा पर रोक लगाने संबंधी संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के विरुद्ध ही मतदान किया था। भारत, ठोस तर्कों के साथ देश की कानूनी व्यवस्था के अनुसार इस मसौदे के खिलाफ अपनी रखता आया है। इस वर्ष मेक्सिको की ओर से पेश किया गया यह प्रस्ताव सभी देशों से मृत्युदंड को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाने का अनुरोध लिए था। इसमें जिन देशों ने मृत्युदंड समाप्त कर दिया है, उनसे इसे दोबारा लागू नहीं करने की अपील भी शामिल थी। गौरतलब है कि 193 सदस्य देशों में से 133 ने इस प्रस्ताव समर्थन किया है। वहीं, 33 देशों ने इसके खिलाफ अपनी वोट किया। 16 देश संयुक्त राष्ट्र महासभा में आए इस प्रस्ताव के मतदान से अनुपस्थित रहे। वस्तुतः हर देश की अपनी एक न्यायिक प्रक्रिया होती है। आपराधिक मामलों की जांच और सजा के नियम कायदे होते हैं। देश में बढ़ रहे बर्बर अपराधों के आंकड़े बताते हैं कि सजा देने के मामले में सख्ती आवश्यक है। बावजूद इसके हमारे देश में केवल दुर्लभतम मामलों में ही फांसी की सजा सुनाई जाती है। ऐसे में अपने देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और संप्रभु अधिकारों के प्रति समझौता नहीं किया जा सकता। इसी के चलते मृत्युदंड की सजा के विरुद्ध पूरी दुनिया में कोई आम सहमति बनना वाकई मुश्किल है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी इस पर चिंता जताई गई कि मृत्युदंड देने के विचार को सीमित करने के प्रयासों को बल देने के बावजूद 2025 में फांसी दिए जाने के दर्ज मामले बढ़े हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल दुनिया के 17 देशों में करीब 2,707 लोगों को डेथ पैनल्टी की सजा दी गई। यही वजह है कि वैश्विक स्तर पर सभी देशों को साथ लाने की कोशिशें की जा रही हैं। समझना जरूरी है कि अमानवीय अपराध के लिए दी गई कठोर सजा को केवल अपराधी के मानवाधिकारों से जोड़ना उचित नहीं। इस आपराधिक प्रवृत्ति के शिकार हुए लोगों और उनके परिवारों के मानवाधिकारों को लेकर सोचना भी जरूरी है। साथ ही यह समाज के हर नागरिक एक मन में एक भरोसा पोसने से जुड़ा मामला भी है। यही वजह है कि हमारे देश में सबसे गंभीर अपराधों के लिए यह सर्वोच्च कानूनी सजा देने का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के कई ऐतिहासिक फैसले बताते हैं कि मृत्युदंड अत्यंत क्रूर अपराध और सुधार या पुनर्वास की कोई संभावना न बचने की स्थिति में ही दिया जाता है। देश में आखिरी बार तिहाड़ जेल में 20 मार्च 2020 को फांसी दी गई थी। 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड के दोषियों को मृत्युदंड दिया गया था। अमानवीय, क्रूर और निर्ममता की सारी सीमायें पार करने वाली सामूहिक दुष्कर्म की इस घटना ने आमजन को भीतर तक झकझोर दिया था। वैश्विक स्तर पर भी भारत को 'रेप केपिटल' और सबसे असुरक्षित देश तक कहा गया। तब दोषियों को फांसी देने का फैसला पूरे समाज की पीड़ा और आक्रोश के लिए मरहम के समान रहा। इससे पहले 2012 में 26 नवंबर, 2008 को हुए आतंकवादी हमले में शामिल कसाब को फांसी दी गई थी। ऐसे में अपने देश की स्वतंत्र न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करने के संप्रभु अधिकार और समाज में विश्वास बनाये रखने हेतु भारत का यह स्पष्ट रुख आवश्यक था।

(लेखिका स्वतंत्र स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

सजगता से दूर होती है चिंता



जब तुम चिंता का अनुभव करो, बहुत चिंताग्रस्त हो जाओ, तब इस विधि का प्रयोग करो। इसके लिए क्या करना होगा? जब साधारणतः तुम्हें चिंता घेरती है, तब तुम क्या करते हो? तुम उसका हल ढूंढ़ते हो। उसके उपाय खोजते हो। लेकिन ऐसा करके तुम और भी चिंताग्रस्त हो जाते हो। तुम उपद्रव को बढ़ा लेते हो, क्योंकि विचार से चिंता का

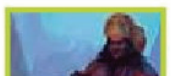


संकलित

दर्शन

समाधान नहा हा सकता ह। ावचार क द्वारा ाचता का ावसजन नहा हा सकता ह, क्योंकि विचार स्वयं एक तरह की चिंता है। यह विधि बहुत आसान है। यह कहती है कि चिंता के साथ कुछ मत करो। सिर्फ सजग हो जाओ। मैं तुम्हें एक दूसरे जेन गुरु बोकोजू के संबंध में एक पुरानी कहानी सुनाता हूं। वह एक गुफा में अकेले रहते थे, बिल्कुल अकेले। लेकिन दिन में या कभी-कभी रात में भी वह जोरों से कहता थे, 'बोकोजू'। यह उनका अपना नाम था। और फिर वह खुद कहते, 'हां महोदय, मैं मौजूद हूं।' जबकि वहां कोई दूसरा नहीं होता था। उनके शिष्य उससे पूछते थे, 'क्यों आप अपना ही नाम पुकारते हैं और फिर खुद कहते हैं, हां, मैं उपस्थित हूं?' बोकोजू ने कहा, 'जब भी मैं विचार में डूबने लगता हूं तो मुझे सजग होना पड़ता है। इसीलिए मैं अपना नाम पुकारता हूं। जिस क्षण मैं बोकोजू कहता हूं और कहता हूं कि हां महाशय, मैं मौजूद हूं, उसी क्षण विचारणा, चिंता विलीन हो जाती है।' फिर अपने अंतिम दिनों में, आखिरी दो-तीन वर्षों में उन्होंने कभी अपना नाम नहीं पुकारा और न ही यह कहा कि हां, मैं मौजूद हूं।

पांच मिनट का जीवन



एक बार एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल गए वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं सका। यमराज ने पीने के लिए व्यक्ति से पानी मांगा, बिना एक क्षण गंवाए उसने पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने बताया कि वो उसके प्राण लेने आये हैं लेकिन चूंकि तुमने मेरी प्यास बुझाई है इसलिए मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूं। यह कहकर



संकलित

प्रेरणा

यमराज न एक डायरा दकर उस आदमा स कहा ाक तुम्हार पास 5 ामनट का समय ह। इसमें तुम जो भी लिखोगे वही हो जाएगा लेकिन ध्यान रहे केवल 5 मिनट। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा तो उसने देखा कि पहले पेज पर लिखा था कि उसके पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है और वह करोड़पति बनने वाला है। उसने वहां लिख दिया कि उसके पड़ोसी की लॉटरी न निकले। अगले पेज पर लिखा था कि उसका एक दोस्त चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है, तो उसने लिख दिया कि उसका दोस्त चुनाव हार जाए। इस तरह, वह पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ से डायरी ले ली और कहा वत्स तुम्हारा पांच मिनट का समय पूरा हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने अपने पूरे 5 मिनट का समय दूसरों का बुरा करने में व्यतीत कर दिया और अपना जीवन खतरे में डाल दिया, अंततः तुम्हारा अंत निश्चित है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत पछताया लेकिन सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल चुका था।

अंतर्मन



आज की पाती

नदियों को प्रदूषित करने पर सख्त कार्रवाई जरूरी

आजकल नदियों में प्रदूषण बढ़ने की खबर सुर्खियों में है। रायपुर और इसके साथ लगते क्षेत्रों में जहां भी नदियां बह रही है, उसमें पानी की गुणवत्ता बहुत खराब हो गई है। इसके लिए अदालत ने भी कहा है कि करोड़ों रुपए इसकी सफाई पर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें प्रदूषण बढ़ रहा है। कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए प्रदूषण के जिम्मेदार लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा और संबंधित विभाग के अधिकारियों से भी इसकी वसूली की जाएगी। क्योंकि सरकारें और संबंधित विभाग नदियों की सफाई के प्रति ढुलमुल रवैया अपनाते हैं। तभी तो कुछ तत्व बेखौफ होकर इन्हें प्रदूषित करते हैं। नदियों को प्रदूषित करने पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। - पवन गहलोत, रोहतक

ट्रेंड

बेहतरीन तालमेल



कुलगाम में लश्कर के घाटी में मौजूद आखिरी सक्रिय स्थानीय आतंकवादी, लतीफ भट को मार गिराया गया। उससे एक दिन पहले, कुलगाम में ही उसके एक साथी आतंकवादी, उमर निसार को भी मार गिराया गया था। इस पूरे ऑपरेशन में बेहतरीन तालमेल देखने को मिला।

- अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

स्केटर सृष्टि को बधाई



महाराष्ट्र की युवा स्केटर सृष्टि शर्मा ने लिम्बो स्केटिंग में 50 मीटर की दूरी सिर्फ 6.86 सेकंड में तय करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हमें सृष्टि के कौशल और प्रदर्शन पर गर्व है। सृष्टि को हार्दिक बधाई!

- देवेंद्र फडणवीस, सीएम, महाराष्ट्र

अनुशासनहीनता अस्वीकार्य



पुलिस की वर्दी में अनुशासनहीनता और कदाचार किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। पुलिस बल में अनुशासन, जवाबदेही और ईमानदारी सर्वोपरि है। 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित करने के आदेश दिए हैं। - डॉ. मोहन यादव, सीएम, मध्यप्रदेश

मोदी का वादा



मोदी जी ने महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि आम आदमी की थाली छोटी होती जा रही है, जेबें खाली हो रही हैं, और घर का खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा है। 2014 में महंगाई कम करने का वादा, 2026 में लोगों की जेबों पर डाका।

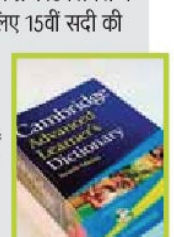
- मल्लिकार्जुन खड़गे, अध्यक्ष, कांग्रेस



करंट अफेयर

कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 'ह्यूमन' को चुना वर्ष 2026 का शब्द

कृत्रिम मेधा (एआई) को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच 'कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 'ह्यूमन' डिक्शनरी' ने 2026 के उस शब्द के चयन के लिए 15वीं सदी की ओर रुख किया है, जो मौजूदा सांस्कृतिक और सामाजिक माहौल को सबसे बेहतर ढंग से बयां करता है। डिक्शनरी ने 'ह्यूमन' (मानव) को 2026 का शब्द चुना है। यह चयन केवल अतीत की ओर लौटने का संकेत नहीं है, बल्कि एआई के कारण मशीनों और इंसानों के बीच धुंधली होती सीमाओं को लेकर चल रही बहस का भी प्रतिबिंब है। डिक्शनरी के शब्दकोश विशेषज्ञ कॉलिनमैकिंटोश ने कहा, ''एआई हमारे मानव होने के अर्थ को लेकर बातचीत का तरीका बदल रहा है। सोचने की क्षमता एआई को सौंपने से इंसान क्या खो सकते हैं, इस चिंता ने हमें एआई पर अपनी निर्भरता के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर किया है। यह चिंता बड़े गणितज्ञों से लेकर छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों तक में है।' लैटिन भाषा के शब्द 'ह्यूमनस' से बना शब्द 'ह्यूमन' 1450 के दशक से इस्तेमाल में है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार, इसका अर्थ है- ऐसे गुणों, कमियों और भावनाओं से युक्त होना, जो इंसानों में होती हैं और जो उन्हें देवताओं, जानवरों या मशीनों से अलग करती हैं।



ऑफ बीट

अंटार्कटिका में जूतों के निशान भी पहुंचा सकते हैं नुकसान

जंगलों और प्राकृतिक क्षेत्रों में घूमने जाने वाले लोगों को आमतौर पर सलाह दी जाती है कि वे वहां केवल अपने पैरों के निशान छोड़कर आएं। हालांकि, एक नए अध्ययन में सामने आया है कि अंटार्कटिका में पैरों के निशान भी दुर्लभ पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनमें ऐसे बदलाव ला सकते हैं, जिनकी भरपाई संभव नहीं है। अंटार्कटिका में दुनिया के कुछ सबसे दुर्लभ और महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद हैं। इनमें मैकमुर्डो ड्राई वैलीज की विशाल बर्फ-मुक्त भूमि की स्थायी रूप से जमी मिट्टी भी शामिल है। यह पृथ्वी के सबसे शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में से एक है। कठोर जलवायु परिस्थितियों के बावजूद यहां बर्फ से जमी मिट्टी की परतों में विशिष्ट सूक्ष्मजीव समुदाय और नेमेटोड, टार्डिग्रेड तथा रोटिफर जैसे छोटे अकशेरुकी जीव पाए जाते हैं। ये जीव रेत के कणों के आसपास मौजूद पानी की बेहद पतली परतों में जीवित रहते हैं। अंटार्कटिका के पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर दिया जाता है। इसके तहत वहां जाने से पहले जूतों और अन्य उपकरणों की व्यापक जांच, सफाई और संक्रमणमुक्त करने के नियम लागू हैं। हालांकि, इन नियमों का मुख्य उद्देश्य बाहरी आक्रामक प्रजातियों को अंटार्कटिका में पहुंचने और फैलने से रोकना है।



चुनाव बहिष्कार से लोकतंत्र में जनता का भरोसा टूटेगा, विपक्ष ऐसा नहीं करेगाः राहुल गांधी

बोले लोकसभा में विपक्ष के नेता- हर चोट सहेंगे, हर वोट के लिए लड़ेंगे और देश के सामने रखेंगे सच्चाई

⏭ नई दिल्ली

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने चुनाव में कथित वोट चोरी और चुनावी प्रक्रिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तथा चुनाव आयोग (ईसी) पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने विपक्ष की ओर से चुनाव बहिष्कार किए जाने की मांग पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया कि विपक्ष चुनाव का बहिष्कार नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए भारत का लोकतंत्र सर्वोपरि है। राहुल गांधी ने कहा कि यदि विपक्ष ने चुनाव लड़ना छोड़ दिया तो जनता का लोकतंत्र से भरोसा उठ जाएगा और भाजपा भी यही चाहती है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बार-बार यह सवाल उठाया जाता है कि भाजपा और चुनाव आयोग की कथित वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं कर देता? इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के लिए भारत का लोकतंत्र सबसे पवित्र है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का विश्वास बनाए रखना विपक्ष की जिम्मेदारी है और वह इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा।



भाजपा पर लगाया चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप

उन्होंने कहा कि जिस दिन विपक्ष ने चुनावी लड़ना छोड़ दिया, उस दिन जनता का लोकतंत्र से भरोसा ही उठ जाएगा। राहुल गांधी के मुताबिक भाजपा भी यही चाहती है कि विपक्ष चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो जाए और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का विश्वास कमजोर पड़े। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि विपक्ष ऐसा नहीं होने देगा और लोकतंत्र की रक्षा के लिए चुनावी मैदान में लगातार संघर्ष करता रहेगा। राहुल गांधी ने अपने बयान में विपक्ष के संघर्ष का संकल्प दोहराते हुए कहा कि विपक्ष हर चोट सहेगा, हर वोट के लिए लड़ेगा और हर सच देश के सामने रखेगा।

उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सत्ता हासिल करने की नहीं, बल्कि संविधान की रक्षा करने की है। संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए विपक्ष पहले भी मैदान में था, आज भी है और आगे भी अपनी लड़ाई जारी रखेगा। राहुल गांधी ने यह भी संकेत दिया कि विपक्ष की रणनीति चुनावी प्रक्रिया से अलग होने की नहीं, बल्कि उसमें कथित अनियमितताओं को उजागर करने और जनता के बीच इस मुद्दे पर लगातार संवाद बनाए रखने की है। उनका मानना है कि यदि विपक्ष चुनाव से पीछे हटता है तो इससे पूरी चुनावी प्रक्रिया की वैधता पर सवाल खड़े होंगे और लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होगी।

अमेरिका में भी उठाया चुनावी पारदर्शिता का मुद्दा

राहुल गांधी का यह बयान अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ हुई बातचीत के बाद सामने आया है। 18 नवंबर को हुई इस बातचीत में उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को पवित्र बताते हुए कहा कि लोकतंत्र की व्यवस्था में समस्याओं का आरोप लगाने के लिए उनके पास ठोस प्रमाण होना जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष को चुनाव आयोग के भीतर से भी कुछ जानकारियां मिल रही हैं और आयोग के कुछ वरिष्ठ अधिकारी मौजूदा परिस्थितियों को लेकर असहज हैं। ये राहुल गांधी के अपने दावे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद चुनावी प्रक्रिया से अलग होने का रास्ता नहीं चुना गया है। इसके बजाय विपक्ष चुनाव में भाग लेते हुए कथित गड़बड़ियों को सामने लाने और जनता को जागरूक करने की कोशिश जारी रखेगा।

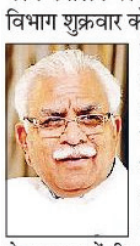
वोट चोरी अभियान के बीच बयान के राजनीतिक मायने

गौरतलब है कि कांग्रेस पिछले कुछ समय से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और चुनावी पारदर्शिता को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। राहुल गांधी कई मौकों पर आरोप लगा चुके हैं कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ियां लोकतंत्र और संविधान के लिए गंभीर चुनौती हैं। भाजपा और चुनाव आयोग को लेकर लगाए गए इन आरोपों पर राजनीतिक विवाद भी जारी है।

खबर संक्षेप

खट्टर आज पीएम स्वनिधि सम्मान पुरस्कार देंगे

नई दिल्ली। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का शहरी विकास विभाग शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित डॉ. आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 का आयोजन करेगा। ये पुरस्कार केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल प्रदान करेंगे। राज्य मंत्री तोखन साहू विशिष्ट अतिथि रहेंगे।



नाबालिग पुत्री/पुत्र के नाम परिवर्तन के मामले में (अभिभावक/पालक द्वारा प्रमाणित)

मै मनोहर दास (माता/पिता/पालक का नाम) सुपुत्र/सुपुत्री मनोहर दास गाँव/शहर सराईटोला पो. शेखरपुर तहसील पत्थलगांव जिला जशपुर छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने नाबालिग,सुपुत्र/सुपुत्री का नाम कसिक महान्त(पुराना नाम) से बदल कर कशिश महंत (नया नाम) रख लिया है।

मनोहर दास

माता/पिता/पालक के हस्ताक्षर

नाम सुधार/परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं प्रेमांशु तिर्की पिता श्रीराम तिर्की, निवासी- ग्राम बकलो, पोस्ट- करजी, तहसील व थाना- दरिमा, जिला- सरगुजा (छ.ग.) का स्थायी निवासी हूँ। मेरे आधार कार्ड क्रमांक xxxx-xxxx-5540 में त्रुटिवश मेरा नाम प्रेमांशु (PREMANSHU) पिता श्रीराम (SRIRAM) दर्ज हो गया है, जबकि मेरी कक्षा 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची में मेरा सही नाम प्रेमांशु तिर्की (PREMANSHU TIRKEY) पिता श्रीराम तिर्की (SHREERAM TIRKEY) दर्ज है। दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। मैंने दिनांक 20/11/2026 को नोटरी के समक्ष शपथ पत्र निष्पादित कर लिया है। भविष्य में मुझे सभी दस्तावेजों में प्रेमांशु तिर्की पिता श्रीराम तिर्की के नाम से जाना, पढ़ा व समझा जावे।

शपथकर्ता

प्रेमांशु तिर्की, पिता श्रीराम तिर्की निवासी- ग्राम बकलो, पोस्ट- करजी, तहसील व थाना- दरिमा, जिला- सरगुजा (छ.ग.)

ग्रीन गैस की केवाईसी के नाम पर साइबर ठगी

सरोजनीनगर, लखनऊ। बंथरा थाना क्षेत्र में करीब एक माह पहले ग्रीन गैस की केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर साइबर जालसाजों ने एक व्यक्ति के बैंक खाते से करीब तीन लाख रुपये पार कर दिए।

मौसम विभाग ने कहा- अब तूफान अकवन ओडिशा की ओर चला

नई दिल्ली। भारतीय मौसम विभाग ने पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर मौजूद भीषण चक्रवाती तूफान अकवन के तीव्र होने की खबर दी है। अकवान पिछले 6 घंटों के दौरान 17 किमी प्रति घंटे की गति से



उत्तर की ओर बढ़ा है। गुरुवार को11:30 बजे यह उसी क्षेत्र में, 15.4अंस उत्तर अक्षांश और 85.2अंश पूर्व देशांतर के पास स्थित था। यह आंध्र प्रदेश से लगभग 390 किमी पूर्व-दक्षिण-पूर्व, कलिंगपट्टनम से 350 किमी दक्षिण-दक्षिण-पूर्व, गोपालपुर (ओडिशा) से 430 किमी दक्षिण, पुरी से 490 किमी दक्षिण और चेन्नई (तमिलनाडु) से 600 किमी पूर्व-उत्तर-पूर्व में है। बुधवार से इसने रास्ता बदल लिया। और ओडिशा की ओर बढ़ने लगा।

एक घंटे से ज्यादा समय तक चली बैठक में ईरान व यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा हुई

» दुनियाभर के मुद्दों पर तीन महाशक्तियों अमेरिका, रूस व चीन ने किया मंथन

एटमी हथियारों पर प्रतिबंध, जंग खत्म कर होर्मुज की आवाजाही 'बहाल' करनी होगी

- चीन-अमेरिका-रूस ने न्यूक्लियर बातचीत करने और इसके दुनिया के अन्य देशों में जाने से रोकने का वादा किया



जिनपिंग ने ट्रंप को दिया सहारा

एजेंसी ⏭ बीजिंग

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बैठक खत्म हो चुकी है। एक घंटे से ज्यादा समय तक चली इस बैठक में परमाणु हथियारों और ईरान, यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा हुई। चीन-अमेरिका-रूस ने न्यूक्लियर बातचीत करने और इसके दुनिया के अन्य देशों में जाने से रोकने का वादा किया। होर्मुज स्ट्रेट से तेल की आवाजाही जारी रखने में भी तीनों देश सहमत दिखे।

परमाणु युद्ध में किसी की भी जीत नहीं हो सकती और इसे कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए



डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन चर्चा करते हुए

यूक्रेन के अलावा ईरान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की भी इन मुद्दों में हिस्सेदारी पर अनुपस्थिति पर सवाल

परमाणु हथियारों को छोड़ना किसी भी देश के लिए आसान नहीं

त्रिपक्षीय बैठक से पहले ट्रंप ने शी जिनपिंग के साथ अलग से मुलाकात की

ट्रंप ने आईसीसी को लेकर भी उठाया मुद्दा

त्रिपक्षीय बैठक की शुरुआत में ट्रंप ने एक और मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि तीनों देश अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) जैसे संगठनों से अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करने के तरीकों पर भी बात करेंगे। इस बैठक को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ तीन बड़े देशों के नेताओं का एक साथ बैठना अपने आप में किसी समझौते की गारंटी नहीं है। खासकर तब, जब यूक्रेन जैसे युद्ध से सीधे प्रभावित देश बातचीत में शामिल नहीं हैं।

घोषणा पत्रः 3 देश 4 प्रमुख मुद्दों पर सहमत

1. संयुक्त राष्ट्र में सुधार
   - अमेरिका, रूस और चीन संयुक्त राष्ट्र में सुधार की दिशा में काम करेंगे, ताकि यूएन वैश्विक चुनौतियों से ज्यादा प्रभावी ढंग से निपट सके।
2. ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने पर सहमति
   - तीनों देश रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने की योजना बनाएंगे। साथ ही, दुनिया के सभी देशों के हित में ऊर्जा की स्थिर आपूर्ति बनाए रखने के महत्व पर सहमति जताई।
3. आईसीसी के अधिकार क्षेत्र पर सहमति
   - तीनों नेताओं ने कहा कि देशों की सहमति के सिद्धांत और सरकारी अधिकारियों का मिलने वाली कानूनी छूट का सम्मान जरूरी है।
4. परमाणु हथियारों पर बातचीत
   - तीनों देशों ने दोहराया कि परमाणु युद्ध न तो जीता जा सकता है और न ही कभी लड़ा जाना चाहिए।

राहुल विदेश में भारत विरोधी ताकतों के मोहरे की तरह व्यवहार कर रहे

मंत्री रिजिजू बोले- आईएमएफ और विश्व बैंक भारत को बड़ी अर्थव्यवस्था मान रहे पर राहुल गांधी इसे 'मर चुकी अर्थव्यवस्था' का झूठ फैला रहे

⏭ नई दिल्ली

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरन रिजिजू ने बृहस्पतिवार को राहुल गांधी द्वारा शिकागो विश्वविद्यालय में भारत की अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को लेकर दिए गए बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते विदेशी धरती पर जाकर भारत के खिलाफ इस तरह के झूठे और आपत्तिजनक बयान देना अत्यंत शर्मनाक है और कोई भी सच्चा भारतीय अपने देश के खिलाफ ऐसी बातें कभी नहीं करेगा। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी लगातार अपनी पार्टी और विपक्ष को नीचे डुबाने का काम कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी के दावों को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक सहित सभी प्रमुख वित्तीय संस्थान यह मान रहे हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। आईएमएफ हमने नहीं बनाया है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है। आखिर उन्हें कौन समझाए कि वे भारत की तरक्की को नकार कर खुद से और देश की जनता से झूठ बोल रहे हैं।



उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक प्रगति और गरीबी उन्मूलन के ऐतिहासिक रिकॉर्ड का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ल्ड बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2011 से 2023 के बीच भारत में 50 करोड़ से ज्यादा लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं। यह दुनिया में सबसे तेज गति से गरीबी खत्म करने का एक रिकॉर्ड है। कांग्रेस ने 'गरीबी हटाओ' के नारे लगाकर केवल वोट बटोरे और सत्ता सुख भोगा, लेकिन गरीबी कभी नहीं हटाई। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश से गरीबी समाप्त होने की कगार पर है और हम 'विकसित भारत' के रास्ते पर तेजी सेबढ़ रहे हैं। राहुल को नसीहत देते हुए दो महत्वपूर्ण सुझाव दिए। जब उन्हें देश में पूरी आजादी से घूमने और बोलने की स्वतंत्रता है, तो वे विदेश जाकर यह झूठ बोलना बंद करें कि भारत में आजादी खत्म हो गई है। भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया के ग्रोथ का इंजन है, उसे 'मरी हुई अर्थव्यवस्था' कहकर देश को बदनाम न करें।

सांसद महुआ मोइत्रा ने अंडों से हमले को लेकर भाजपा पर लगाए आरोप, सीजेआई से की हस्तक्षेप की मांग

⏭ नई दिल्ली

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और भाजपा के बीच बृहस्पतिवार को आरोप प्रत्यारोपों के बाण चले। मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि गुरुवार को नादिया जिले के कालीगंज ब्लॉक में एक पार्टी कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान उन पर फिर से अंडों से हमला किया गया। उन्होंने इस घटना को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) और कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से हस्तक्षेप की मांग की है। हालांकि भाजपा के नादिया जिला मीडिया संयोजक संदीपन मजूमदार ने मोइत्रा के इन आरोपों को खारिज कर दिया कि उन पर हुए अंडे के हमले के पीछे भाजपा कार्यकर्ता थे। उन्होंने दावा किया कि यह घटना मोइत्रा के खिलाफ जनता के गुस्से का नतीजा है, जो उनके द्वारा अतीत में हिंदू देवी-देवताओं के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणियों की वजह से है।

मोइत्रा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कई वीडियो पोस्ट किए हैं। आरोप है कि कैसे वह और नादिया जिले के कालीगंज विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की विधायक अलीफा अहमद, कालीगंज ब्लॉक में एक पार्टी बैठक में शामिल होने जा रही थीं, तभी भाजपा

- भाजपा ने मोइत्रा के आरोपों को किया खारिज, उसे जनता के गुस्से का नतीजा बताया

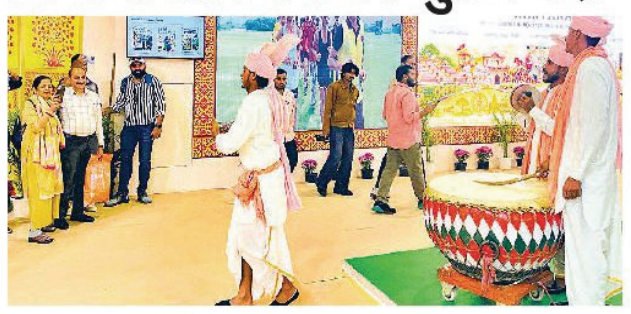
समर्थित लोगों ने उन पर अंडों से हमला कर दिया। अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भारत के मुख्य न्यायाधीश और कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का ध्यान इस मामले की ओर खींचते हुए कृष्णानगर से दो बार की सांसद मोइत्रा ने दावा किया कि उनकी कार को धक्का दिया और उन पर तथा अलीफा अहमद पर लाठियों और अंडों से हमला किया, जबकि पुलिस उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही थी। एक वीडियो संदेश में मोइत्रा ने दावा किया, पुलिस ने मुझसे वहां से चले जाने को कहा। हमें पहले से ही जानकारी थी कि ऐसा हो सकता है, इसलिए हमने वहां जाने से पहले ही पुलिस को बता दिया था। इसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। उसी पोस्ट में, मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसे ही अदालत की अवमानना कहते हैं, जहां पश्चिम बंगाल पुलिस ने भाजपा के साथ मिलकर उन पर फिर से हमला करवाया, जिसे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया था। उन्होंने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को भी चुनौती दी कि वे अदालत में खड़े होकर इस घटना को सही ठहराने की हिम्मत दिखाएं। मजूमदार ने कहा, पश्चिम बंगाल में जब तृणमूल कांग्रेस सत्ता में थी, तब उन्होंने जिस तरह से हिंदू देवी-देवताओं का अपमान किया था। सत्ता बदलने के बाद अब आम लोगों की ओर से यह एक स्वाभाविक विरोध है। उन पर बम नहीं, बल्कि सिर्फ अंडे फेंके गए हैं। उन्होंने अतीत में जो कुछ किया था, उसके लिए अब उन्हें बस इतना ही झेलना पड़ रहा है।

हरियाणवी लोक संस्कृति की गूंज से सराबोर हुआ अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला

बंचारी की नंगाड़ा पार्टी की थाप पर थिरके दर्शक हरियाणा पवेलियन बना आकर्षण का मुख्य केंद्र

⏭ नई दिल्ली

नई दिल्ली में चल रहे भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में हरियाणा सरकार द्वारा बनाया गया हरियाणा पवेलियन इन दिनों कारोबार और कला के साथ-साथ लोक संस्कृति के रंगों का भी केंद्र बन गया है। पवेलियन में बंचारी की नंगाड़ा पार्टी हरियाणवी लोक वाद्य की जोशीली प्रस्तुति दे रही है। नंगाड़े की गूंजती थाप पर बड़ी संख्या में आम लोग खुद को थिरकने से रोक नहीं पा रहे। लोग इन पलों को अपने मोबाइल में कैद करने के लिए सेल्फी और फोटो भी खूब खिंचवा रहे हैं। मेले में देश-विदेश से आने वाले लोग बड़ी तादाद में हरियाणा पवेलियन में पहुंच रहे हैं। यहां प्रदेश की हस्तशिल्प, हथकरघा, कृषि और खाद्य उत्पादों के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत की झलक भी देखने को मिलती है। इसी कड़ी में नंगाड़ा पार्टी की प्रस्तुति ने पवेलियन में नई ऊर्जा भर दी है। जैसे ही नंगाड़ा बजना शुरू होता है, पवेलियन के आसपास से गुजर रहे दर्शकों के कदम खुद-ब-खुद ठिठक जाते हैं और देखते-देखते वहां भीड़ जुट जाती है।



अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला हर वर्ष देश के उद्यमियों, कारीगरों और राज्यों को अपने उत्पाद और पहचान प्रदर्शित करने का बड़ा मंच उपलब्ध कराता है। हरियाणा पवेलियन में प्रदेश की औद्योगिक प्रगति, स्थानीय उत्पादों और कारीगरी के साथ सांस्कृतिक विरासत को भी समान महत्व दिया गया है। नंगाड़ा पार्टी की प्रस्तुति इसी सोच का हिस्सा है कि आने वाले हर व्यक्ति को हरियाणा की समृद्ध परंपरा, लोक कला और जीवंत संस्कृति पवेलियन में नंगाड़ा सेल्फी प्वाइंट की तरह आकर्षण का केंद्र बन गया है।

2014 में 28 लाख हेक्टेयर भूमि को पुनर्जीवित करने का था लक्ष्य, लेकिन खर्च नहीं हो पाया निर्धारित फंड, दिल्ली-एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण और अरावली में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई पर भी जताई चिंता

ग्रीन इंडिया मिशन के लक्ष्य का महज 5 फीसदी हासिल कैग रिपोर्ट पर पीएसी सख्त, पर्यावरण मंत्रालय से मांगा जवाब

⏭ नई दिल्ली

देश में पर्यावरण संरक्षण, वन क्षेत्र के विस्तार और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए शुरू किए गए ग्रीन इंडिया मिशन की प्रगति को लेकर संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने गंभीर नाराजगी जताई है। कांग्रेस महासचिव और लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने बताया कि समिति ने ग्रीन इंडिया मिशन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट की समीक्षा की। इस दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के अधिकारियों को तलब कर उनसे मिशन की प्रगति और इसके क्रियान्वयन में हुई देरी को लेकर जवाब मांगा गया। वेणुगोपाल के अनुसार, समिति ने देश के 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मिशन की स्थिति पर भी चर्चा की। समीक्षा के दौरान मिशन की बेहद धीमी प्रगति और मंत्रालय की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया। समिति का मानना है कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा इतना महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम अपने निर्धारित उद्देश्यों को हासिल करने में गंभीर रूप से पिछड़ रहा है।

28 लाख हेक्टेयर भूमि को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य, उपलब्धि महज पांच फीसदी

केसी वेणुगोपाल ने बैठक के बाद कहा कि वर्ष 2014 में ग्रीन इंडिया मिशन के तहत 28 लाख हेक्टेयर भूमि को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसका उद्देश्य देश में वन क्षेत्र का विस्तार करना, क्षतिग्रस्त वन भूमि को बहाल करना और पर्यावरणीय संतुलन को मजबूत करना था। लेकिन मिशन के लिए निर्धारित धनराशि का अपेक्षित उपयोग नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप अब तक मिशन अपने कुल लक्ष्यों का केवल पांच प्रतिशत ही हासिल कर पाया है। पीएसी ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। समिति की समीक्षा में यह बात सामने आई कि केवल योजनाएं बनाने और लक्ष्य निर्धारित करने से पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। इसके लिए समयबद्ध क्रियान्वयन, पर्याप्त वित्तीय संसाधन और जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है।

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति पर विशेष चिंता

पीएसी ने दिल्ली-एनसीआर में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर चिंता जताई। वेणुगोपाल ने कहा कि राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) का 400 के पार पहुंचना और गंभीर श्रेणी में बने रहना अब सामान्य स्थिति जैसा हो गया है। यह स्थिति लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए बेहद चिंताजनक है। उन्होंने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारणों में अरावली पर्वतमाला और आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई तथा वनों के विनाश को भी एक महत्वपूर्ण कारण बताया। अरावली पर्वतमाला दिल्ली-एनसीआर के पर्यावरणीय संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह क्षेत्र हरित आवरण, जैव विविधता और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के साथ-साथ धूल भरी हवाओं के प्रभाव को कम करने में भी सहायक है। ऐसे में अरावली और आसपास के वन क्षेत्रों का लगातार क्षरण क्षेत्र की पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है।

मंत्रालय से तत्काल ठोस कार्ययोजना पेश करने को कहा

मिशन की खराब प्रगति और दिल्ली-एनसीआर में पर्यावरणीय संकट को देखते हुए पीएसी ने मंत्रालय से तत्काल एक ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा है। समिति ने स्पष्ट किया है कि मंत्रालय को इस संकट से निपटने के लिए केवल आश्वासन देने के बजाय व्यावहारिक और समयबद्ध कदम उठाने होंगे। समिति की अपेक्षा है कि मंत्रालय मिशन के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने, आवंटित धनराशि का प्रभावी इस्तेमाल करने, वन क्षेत्रों के पुनर्जीवन और पर्यावरण संरक्षण के लिए जवाबदेही तय करने की दिशा में स्पष्ट रोडमैप पेश करे।

चक्रवात से प्रभावित किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार : मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन



रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अकवान चक्रवात के कारण फसलों को हुए नुकसान को लेकर किसानों को आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार हर प्रभावित किसान के साथ खड़ी है। किसानों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चक्रवात से हुई फसल क्षति का सर्वेक्षण कराकर सभी पात्र किसानों को नियमानुसार सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान का सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। सर्वेक्षण के आधार पर प्रभावित किसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) 6-4 के प्रावधानों के अंतर्गत पात्रतानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिन किसानों की फसलें बीमित हैं, उन्हें संबंधित फसल बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्र बीमा दावा राशि दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रभावित किसानों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

एक ही रात में 5 ट्रकों से 300 लीटर डीजल चोरी, आरोपी और ढाबा संचालक गिरफ्तार



छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायगढ़। पूंजीपथरा पुलिस ने ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले आरोपी सूरज यादव और चोरी का डीजल खरीदने वाले ढाबा संचालक मुकेश मखीजा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 80 लीटर डीजल और चोरी में प्रयुक्त जाइलो कार जब्त की है। दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

शिकायत पर हुआ खुलासा

17 नवंबर की रात ट्रक चालक शशिकांत उपाध्याय ने ट्रक सड़क किनारे खड़ा कर सोया था। सुबह देखा तो उसकी समेत 5 ट्रकों की टंकी टूटी थी और करीब 300 लीटर डीजल गायब था। रिपोर्ट पर थाना पूंजीपथरा में धारा 303(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज हुआ।

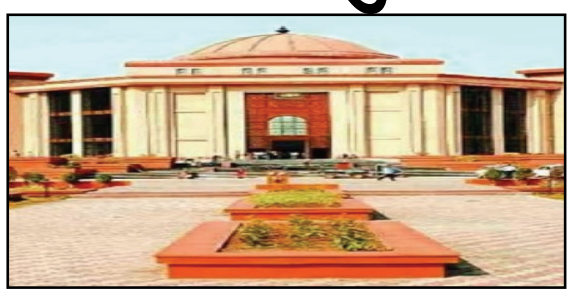
मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया आरोपी

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सूरज यादव (23 वर्ष) को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने बताया कि पैसों की जरूरत के कारण जाइलो कार से रेकी कर 5 ट्रकों की टंकी तोड़कर डीजल ड्रमों में भरा था। कुछ डीजल ट्रक चालकों को और कुछ संबलपुरी स्थित पूजा ढाबा संचालक को बेचा था।

ढाबा संचालक ने खरीदा था चोरी का डीजल

पुलिस ने ढाबा में दबिश देकर संचालक मुकेश कुमार मखीजा (44 वर्ष) को पकड़ा। उसने चोरी का डीजल खरीदना स्वीकार किया। उसके पास से 30 लीटर और सूरज के पास से 50 लीटर डीजल मिला। प्रकरण में धारा 317(2) बीएनएस जोड़ी गई है।

हाईकोर्ट ने हटाई शिक्षक भर्ती परीक्षा पर लगी रोक, साफ हुआ 2 हजार पदों पर नियुक्ति का रास्ता



छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बना असमंजस खत्म हो गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। इस फैसले से राज्य में 2,292 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। लंबे समय से परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को कोर्ट के इस निर्णय से राहत मिली है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की डिवीजन बेंच में हुई।

आरक्षण और दिव्यांग अभ्यर्थियों की पात्रता पर उठे थे सवाल

चिकाकताओं ने राज्य शासन के भर्ती विज्ञापन को चुनौती देते हुए आरक्षण रोस्टर और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए तय शर्तों पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि भर्ती प्रक्रिया में पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया, जो उनके संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। याचिकाकताओं की ओर से दलील दी गई कि सामान्य प्रशासन विभाग के सर्कुलर में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। समाज कल्याण विभाग के सर्कुलर में भी इससे संबंधित दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद भर्ती विज्ञापन में पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया। याचिकाकताओं ने इसे संविधान से मिले अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए भर्ती विज्ञापन को चुनौती दी थी। मामले में कोर्ट को बताया गया कि उसके निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने भर्ती पोर्टल खोलकर दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर दिया था।

कोर्ट की रोक से प्रभावित हुई थी परीक्षा प्रक्रिया

भर्ती परीक्षा के आयोजन की तैयारियां कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पूरी कर ली गई थीं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सहायक शिक्षक पद की परीक्षा 11 अक्टूबर और शिक्षक पद की परीक्षा 25 अक्टूबर को प्रस्तावित थी। हालांकि, कानूनी विवाद और कोर्ट की रोक के चलते परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित हुआ। अब हाईकोर्ट से रोक हटने के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया है। परीक्षा की अगली तारीखों को लेकर अभ्यर्थियों की नजर कर्मचारी चयन आयोग और संबंधित विभाग की आधिकारिक सूचना पर रहेगी।

2,292 पदों पर होनी है भर्ती

छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक एवं शिक्षक भर्ती 2026 के तहत कुल 2,292 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। इनमें ई-संवर्ग के 795 और टी-संवर्ग के 1,497 पद शामिल हैं।

योगी आदित्यनाथ की माताजी के निधन पर सीएम ने जताया शोक

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन



रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूज्य माताजी श्रीमती सावित्री देवी जी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री साय ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर कहा कि माँ का स्थान जीवन में सर्वोपरि होता है। एक पुत्र के लिए माँ ही उसकी पूरी दुनिया होती है। माँ का निःस्वार्थ प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, जिसकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि माताजी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद और पीड़ादायक है। एक माँ का जाना किसी भी व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी और अपूरणीय क्षति होती है, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। योगी आदित्यनाथ जी ने अपने जीवन में माँ के संस्कारों, आशीर्वाद और प्रेरणा से ही सेवा और राष्ट्रधर्म के मार्ग को चुना। उनकी माताजी का जीवन सादगी, त्याग और संस्कारों से परिपूर्ण था। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस दुःखद घड़ी में उनकी गहरी संवेदनाएँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं उनके शोकसंतप्त परिवार के साथ हैं। पूरा छत्तीसगढ़ इस दुःख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री साय ने बाबा केदारनाथ से दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करने तथा शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि शोकाकुल परिवार को धैर्य और संबल प्रदान करें।

पीएम स्वनिधि में छत्तीसगढ़ को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार, फास्टेस्ट मूवर्स में देश में पहला

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। नई दिल्ली में आयोजित 'स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026' में छत्तीसगढ़ को पीएम स्वनिधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। राज्य ने फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में देश में प्रथम और इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज श्रेणी में द्वितीय स्थान हासिल किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दोनों राज्य स्तरीय पुरस्कार ग्रहण किए। समारोह में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और राज्य मंत्री तोखन साहू उपस्थित रहे।

डिजिटल अडॉप्शन में बड़े बचेली प्रथम, दंतेवाड़ा-बिलासपुर द्वितीय

डिजिटल अडॉप्शन श्रेणी में 1 लाख से कम आबादी वाले निकायों में बड़े बचेली को प्रथम और दंतेवाड़ा को द्वितीय स्थान मिला। वहीं 1 से 10 लाख आबादी वाले निकायों में बिलासपुर निगम को द्वितीय स्थान मिला। यह पथ विक्रेताओं को डिजिटल लेनदेन और संस्थागत ऋण से जोड़ने के प्रयासों का परिणाम है।

मुख्यमंत्री ने दी बधाई

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में यह योजना छोटे व्यवसायियों को आत्मनिर्भर बना रही है। 5 पुरस्कार मिलना प्रदेश के लिए गौरव की बात है। विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार का संकल्प है।

उपमुख्यमंत्री ने बताया टीम वर्क का परिणाम

अरुण साव ने कहा कि यह सम्मान नगरीय निकायों की बेहतर कार्यप्रणाली और समर्पण का परिणाम है। योजना से पथ विक्रेताओं को ऋण, डिजिटल लेनदेन और स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। इस दौरान प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, संचालक निलेश महादेव क्षीरसागर, बिलासपुर महापौर पूजा विधानी, दंतेवाड़ा अध्यक्ष पायल गुप्ता और बड़े बचेली अध्यक्ष राजू जायसवाल सहित अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर के दो छात्र दक्षिण कोरिया में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व, सीएम ने दी शुभकामनाएं

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन



रायपुर। रायपुर के वेदिक इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा सातवीं के विद्यार्थी पराक्रम सिन्हा और मोहम्मद गौस अंसारी दक्षिण कोरिया में 28-29 नवंबर को होने वाली रोबोटेक्स इंटरनेशनल ग्रैंड फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोनों ने नेशनल चैंपियनशिप 2026 की लेगो लाइन फॉलोअर श्रेणी में द्वितीय स्थान हासिल किया था। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 16 से अधिक राज्यों के 7 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों और 500 से अधिक रोबोट्स ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 36 विद्यार्थियों का अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। लेगो लाइन फॉलोअर में रोबोट को ट्रैक पर बनी लाइन को पहचानकर आगे बढ़ना होता है, जिसके लिए प्रोग्रामिंग और तार्किक सोच जरूरी होती है। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दोनों विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, उन्हें सही अवसर और मार्गदर्शन मिले तो वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकते हैं।

अवैध धान भंडारण पर प्रशासन की सख्ती, चार प्रतिष्ठानों से 245.60 क्विंटल धान जब्त

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन



धमतरी। नगरी क्षेत्र में राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने चार प्रतिष्ठानों पर छापा मारकर कुल 614 कट्टा यानी 245.60 क्विंटल धान जब्त किया। कलेक्टर के निर्देश पर हुई जांच में दस्तावेजों में अनियमितता मिलने पर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।

कहां से कितना धान जब्त

बेलरगांव में भानुराम साहू के गोदाम से 81 कट्टा, 32.40 क्विंटल, गट्टासिल्ली में एसके फूड्स मिल से 233 कट्टा, 93.20 क्विंटल, गट्टासिल्ली में सफीका धान कुटाई केंद्र से 140 कट्टा 56 क्विंटल, गेदरा में रजा राइस इंडस्ट्रीज से 160 कट्टा, 64 क्विंटल धान जब्त किया गया। जब्त धान संचालकों की सुपुर्दगी में रखा गया है। कार्रवाई में भानुराम साहू, आसिफ मेमन, जावेद मेमन एवं जमीला बानो के नाम शामिल हैं।

समर्थन मूल्य खरीदी में पारदर्शिता के लिए सघन जांच

प्रशासन ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को पारदर्शी रखने के लिए भंडारण स्थलों, राइस मिलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन जांच जारी है। इसका उद्देश्य अवैध धान को खरीदी व्यवस्था में खपाने से रोकना और असली किसानों को योजना का लाभ दिलाना है।

अनियमितता पर होगी कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अवैध भंडारण, अनधिकृत परिवहन और बिचौलियों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। आगे भी संयुक्त जांच दल निरीक्षण जारी रखेंगे, ताकि खरीदी प्रक्रिया निष्पक्ष और किसान हितैषी बनी रहे।

अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दूधिया की मौत

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

लखनऊ। बहन को मौसी के घर छोड़कर बाइक से वापस लौट रहे दूधिया की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। हादसे में युवक के सिर में गंभीर चोट आई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस उसे आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलिहाबाद ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद टक्कर मारने वाला वाहन चालक मौके से फरार हो गया। हरदोई जनपद के कछौना थाना क्षेत्र के टिकवामऊ निवासी शौकत (35) बृहस्पतिवार शाम करीब साढ़े तीन बजे अपनी बहन शबनम को लखनऊ फरीदीपुर में मौसी के घर छोड़कर बाइक से वापस घर लौट रहा था। वह रहीमाबाद थाना क्षेत्र के भतोइया गांव के पास ओवरब्रिज के पास पहुंचा ही था कि तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि शौकत उछलकर सड़क पर दूर जा गिरा। हादसे में उसके सिर में गंभीर चोट आई और बाइक का अगला हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची रहीमाबाद पुलिस घायल शौकत को सीएचसी मलिहाबाद ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिजनों को सूचना देने के बाद शव का पंचनामा भरकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक शौकत अपने भाई शरीफ के साथ लखनऊ में रहकर दूध डेयरी चलाता था। मृतक के पिता सुमेर, मां हंसाना और भाई जमील व शरीफ का रो-रोकर बुरा हाल है। इस संबंध में रहीमाबाद इंस्पेक्टर अरुण कुमार त्रिगुणयाक ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, आसपास लगे सीसीटीवी के माध्यम से टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश की जा रही है।

चेकिंग में रोका तो गाली देकर टीआई को मारी टक्कर, आरोपी ड्राइवर फरार

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जांच के दौरान राजधानी रायपुर में ट्रैफिक थाना प्रभारी को ही टक्कर मारकर ड्राइवर फरार हो गया। घटना में घायल टीआई का अस्पताल में उपचार कराया गया, वहीं आरोपी ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। घटना 16 नवंबर की रात करीब 9:45 बजे की है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर यातायात पुलिस की टीम शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जांच कर रही थी। यातायात थाना नया बस स्टैंड भाठागांव के निरीक्षक एवं प्रभारी नवल किशोर कश्यप अपनी टीम के साथ कुशालपुर चौक से भाठागांव की ओर आने वाली सर्विस रोड पर वाहनों की जांच कर रहे थे। टीम में प्रधान आरक्षक अभयराव, आरक्षक मनोज सावड़े सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। जांच के दौरान टाटा एस वाहन क्रमांक सीजी 04 क्यूसी 0865 वहां पहुंचा। निरीक्षक नवल किशोर कश्यप ने वाहन चालक को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने रुकने की बजाय पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। उसने धमकी दी कि रास्ते से नहीं हटे तो गाड़ी चढ़ा देगा। इसके बाद वह पुलिसकर्मियों को टक्कर मारते हुए वाहन लेकर आगे बढ़ गया। वाहन चालक को रोकने के लिए निरीक्षक नवल किशोर कश्यप उसके पीछे दौड़े। इस दौरान चालक ने वाहन को लहराते हुए चलाया और निरीक्षक को टक्कर मार दी। इससे उनके बाएं टखने, बाएं घुटने, बाईं जांघ और पीठ में चोट आई। घटना के बाद चालक गाली-गलौज करते हुए वाहन लेकर फरार हो गया। जांच में टाटा एस के चालक के तौर पर आशीष देवांगन पिता राजकुमार देवांगन, निवासी महादेव तालाब के पास पुराना चंगोराभाठा, थाना डीडीनगर की पहचान सामने आई। इसके बाद निरीक्षक नवल किशोर कश्यप की लिखित शिकायत पर पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 121(1), 132, 221, 296 और 351(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। मामले की जांच उपनिरीक्षक जगदंबा तिवारी कर रही हैं।

जिला पंचायत की 10 नई दुकानों की नीलामी 11 दिसम्बर को

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज ने जिला पंचायत परिसर के बगल में सेमली मोड़, ग्राम भनौरा में बनी 10 नई दुकानों की नीलामी के लिए सूचना जारी की है। नीलामी 11 दिसम्बर 2026 (शुक्रवार) को दोपहर 12 बजे जिला पंचायत के सभाकक्ष में होगी।

हर दुकान का आकार 3.90×4.20 वर्गमीटर है। प्रति दुकान ऑफसेट प्राइज 1,55,100 रुपये, मासिक किराया 2,200 रुपये और अमानत राशि 15,500 रुपये तय की गई है। दुकानों में अनुसूचित जनजाति के लिए 6 (इनमें 1 दिव्यांगजन और 1 महिला के लिए), अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 और अनारक्षित वर्ग के लिए 2 दुकानें रखी गई हैं।

अमानत राशि केवल एफडीआर, बैंक ड्राफ्ट या टीडीआर के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के नाम से 7 दिसम्बर तक कार्यालयीन समय में जमा की जा सकेगी। नकद राशि स्वीकार नहीं होगी, और हर दुकान के लिए अलग अमानत राशि जमा करनी होगी। नीलामी में 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति भाग ले सकेंगे। दुकान 3 वर्ष के लिए किराये पर दी जाएगी और इनमें मांस, मछली व शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।

अर्नब के बाद क्षेत्र में अक्कान का असर, सुबह से शाम तक होती रही बारिश, भींगा खेतों में पड़ा धान



प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र में शुक्रवार को चक्रवात अक्कान के प्रभाव से सुबह से लेकर शाम तक रुक-रुककर बारिश होती रही। अचानक बदले मौसम के मिजाज से क्षेत्र में ठंड का असर भी काफी बढ़ गया। ग्रामीण अंचलों में लोग दिनभर ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए। वहीं बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता एक बार फिर बढ़ा दी है। खेतों में कटकर पड़ी धान की फसल बारिश में भीगने लगी है, जिससे उसके खराब होने की आशंका बनी हुई है। गौरतलब है कि इससे पहले अक्टूबर माह में चक्रवात अर्नब के प्रभाव से हुई तेज बारिश ने क्षेत्र के किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया था। उस दौरान खेतों में खड़ी धान की फसल के साथ कटकर रखी उपज भी बारिश की चपेट में आ गई थी। किसान अभी पिछली बारिश से हुए नुकसान से उबर भी नहीं पाए थे कि नवंबर में चक्रवात अक्कान के प्रभाव से दोबारा बारिश शुरू हो गई। लगातार मौसम की मार से किसानों की मेहनत पर पानी फिरने की स्थिति बन गई है। क्षेत्र के कई किसानों ने धान की कटाई कर फसल को खेतों में ही छोड़ दिया था। वहीं कई किसानों की धान की फसल अभी खेतों में खड़ी है। शुक्रवार सुबह से हो रही बारिश के कारण खेतों में पानी भरने लगा है। खेतों में पड़ी कटी हुई धान की फसल लगातार भीग रही है। यदि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो धान के सड़ने, अंकुरित होने और उसकी गुणवत्ता खराब होने की आशंका है। इसका सीधा असर किसानों की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। इसके अलावा सब्जी की खेती करने वाले किसानों को भी अपनी फसल खराब होने की चिंता सताने लगी है।

पिछले नुकसान की भरपाई नहीं, फिर मौसम की मार

किसानों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि पिछली बारिश से हुए फसल नुकसान को लेकर अब तक उन्हें कोई ठोस राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। किसानों का कहना है कि खेती में बीज, खाद, मजदूरी और अन्य संसाधनों पर काफी खर्च करने के बाद फसल तैयार होती है, लेकिन कटाई के समय लगातार बारिश होने से पूरी मेहनत बर्बाद होने का खतरा बना हुआ है। पिछली प्राकृतिक आपदा के नुकसान से किसान संभल भी नहीं पाए थे कि दोबारा बारिश ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

ग्रामीण किसानों ने जिला प्रशासन और कृषि विभाग से मांग की है कि चांदनी बिहारपुर क्षेत्र के प्रभावित गांवों में तत्काल फसल नुकसान का सर्वे कराया जाए। पिछली बारिश से हुए नुकसान के साथ वर्तमान बारिश से प्रभावित खेतों का भी आकलन कराकर पात्र किसानों को उचित मुआवजा एवं राहत प्रदान की जाए। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने पहल नहीं की तो लगातार प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे किसानों के सामने आर्थिक संकट और गहरा सकता है।

जिला प्रशासन की अभिनव पहल 'कौशल दान अभियान'

कलेक्टर के नेतृत्व में जनभागीदारी से कौशल विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले में जनभागीदारी को सशक्त बनाने तथा नागरिकों की प्रतिभा, ज्ञान और अनुभव का समाजहित में सदुपयोग करने की दिशा में कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा 'कौशल दान अभियान' की अभिनव पहल की गई है। इस अभियान का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में दक्ष एवं अनुभवी नागरिकों को एक साझा मंच प्रदान कर उनके कौशल और विशेषज्ञता का लाभ समाज के अन्य वर्गों तक पहुंचाना है। इसके माध्यम से स्वैच्छिक सेवा, सामुदायिक सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान की संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाएगा।

अभियान के अंतर्गत शिक्षण, संगीत, नृत्य, खेल, जिम एवं फिटनेस, कंप्यूटर, स्वास्थ्य, कला, तकनीकी कार्य, कृषि, व्यवसाय सहित विभिन्न क्षेत्रों में विशेष दक्षता रखने वाले नागरिक स्वयंसेवक के रूप में अपनी सेवाएं दे सकेंगे। इच्छुक नागरिक अपनी रुचि, उपलब्ध समय एवं विशेषज्ञता के अनुरूप योगदान देकर दूसरों को नए कौशल सीखने और अपनी क्षमताओं को विकसित करने में सहयोग कर सकेंगे। कौशल दान अभियान के माध्यम से जिले में उपलब्ध मानवीय संसाधनों, स्थानीय प्रतिभाओं और व्यावहारिक अनुभवों को समाज के व्यापक हित से जोड़ने का प्रयास किया



जाएगा। यह पहल नागरिकों को अपने ज्ञान एवं हुनर को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को भी सुदृढ़ करेगी। अभियान से विशेष रूप से युवाओं एवं कौशल सीखने के इच्छुक नागरिकों को अनुभवी व्यक्तियों के मार्गदर्शन का अवसर मिल सकेगा।अभियान में सहभागिता करने वाले स्वयंसेवकों के योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सम्मान की व्यवस्था भी की गई है। इसके अंतर्गत प्रतिमाह उत्कृष्ट योगदान देने वाले स्वयंसेवक को 'महीने का स्वयंसेवक' के रूप में सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उल्लेखनीय एवं उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले स्वयंसेवकों को जिला प्रशासन द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा।

ऑनलाइन पंजीयन से जुड़ सकेंगे नागरिक

कौशल दान अभियान से जुड़ने के इच्छुक नागरिक ऑनलाइन पंजीयन के माध्यम से स्वयंसेवक के रूप में अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। पंजीयन प्रक्रिया सरल एवं सुविधाजनक रखी गई है, जिसे लगभग दो मिनट में पूरा किया जा सकता है। जिला प्रशासन ने जिले के शिक्षकों, कलाकारों, खिलाड़ियों, तकनीकी विशेषज्ञों, उद्यमियों, कृषकों एवं विभिन्न क्षेत्रों में दक्ष नागरिकों से अभियान में अधिक से अधिक सहभागिता करने की अपील की है।

सुरक्षित आहार हमारा अधिकार अभियान के तहत होटलो एवं रेस्टोरेंट का किया गया निरीक्षण

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। सुरक्षित आहार हमारा अधिकार थीम के तहत जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट एवं मिठाई दुकानों का निरीक्षण लगातार किया जा रहा है।

नियंत्रक के निर्देशानुसार कलेक्टर श्रीमती रेना जमील, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह तथा अभिहित अधिकारी श्रीमती पुष्पराज चौहान के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री



रामप्रकाश जायसवाल एवं सुश्री दीपा साहू द्वारा जिले के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गोलू स्वीट्स, पंडित स्वीट्स महगवां, बना होटल, बंसल स्वीट्स , गंगा स्वीट्स , मद्रास कॉफी हाउस, साहू स्वीट्स चंदरपुर, गुड्डू होटल चंदरपुर एवं रजवाड़े होटल बसदेई का निरीक्षण किया गया। इस दौरान खुले एवं बिना ढके रखे सांभर तथा पुराने व बासी मिठाइयों को मौके पर नष्ट कराया गया।

समावेशी नीति संकल्प' कार्यशाला में शामिल हुई मंत्री लक्ष्मी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से प्राप्त किया मार्गदर्शन

वंचित एवं कमजोर वर्गों के उत्थान, सामाजिक सशक्तीकरण और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर हुआ मंथन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ शासन की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने 19 नवंबर को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित 'समावेशी नीति संकल्प' समाज कल्याण मंत्रियों की कार्यशाला में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भेंट कर समाज कल्याण एवं वंचित वर्गों के उत्थान से जुड़े विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के समाज कल्याण मंत्रियों ने समाज के वंचित, शोषित एवं कमजोर वर्गों के समग्र उत्थान और सशक्तीकरण से जुड़ी योजनाओं पर विचार-विमर्श किया। साथ ही विभिन्न राज्यों की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों एवं सफल नवाचारों को साझा किया गया, ताकि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के



अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुँचाया जा सके। कार्यशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित 'एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय' एवं 'स्टैंड-अप इंडिया' जैसी महत्वपूर्ण पहलों के माध्यम से शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। इन योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं वंचित वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों को भी रेखांकित किया गया।

इस अवसर पर मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तीकरण, कुपोषण मुक्ति, मातृ एवं शिशु कल्याण तथा समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों के उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों और योजनाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला से प्राप्त मार्गदर्शन एवं विभिन्न राज्यों के अनुभव छत्तीसगढ़ में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और प्रभावी परिणाम सुनिश्चित करने में उपयोगी सिद्ध होंगे। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के विचारों से समाज के प्रत्येक वंचित एवं जरूरतमंद व्यक्ति तक विकास और कल्याण की योजनाओं का लाभ पहुँचाने के संकल्प को और मजबूती मिलेगी। हमारा लक्ष्य विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। कार्यशाला के दौरान आयोजित विशेष सत्रों एवं रात्रिभोज में भी मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने सहभागिता की। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल एवं गुरु खुशवंत साहेब सहित विभिन्न राज्यों के मंत्रीगण उपस्थित रहे।

दो महीने से 11 हाथियों का दल क्षेत्र में जमाये हुए है डेरा

गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों में विचरण कर रहा झुंड, सैकड़ों किसानों की धान सहित अन्य फसलें की चौपट

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

चांदनी बिहारपुर। क्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी लगातार बनी हुई है। करीब दो महीने से 12 जंगली हाथियों का दल क्षेत्र के जंगलों में डेरा जमाए हुए था। वहीं लगभग एक सप्ताह पहले एक हाथी के शावक की मौत हो जाने के बाद अब दल में 11 हाथी शेष बचे हैं। हाथियों का यह दल गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के पार्क परिक्षेत्र अंतर्गत जंगलों में विचरण कर रहा है। वर्तमान में इन हाथियों की मौजूदगी छतरंग के आसपास के जंगलों में बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, चांदनी बिहारपुर क्षेत्र के जंगलों में पिछले करीब दो महीने से हाथियों का दल लगातार आवाजाही कर रहा है। इस दौरान एक सप्ताह पहले गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के पार्क परिक्षेत्र अंतर्गत जंगल में एक हाथी के शावक का शव मिला था। शावक की मौत के बाद हाथियों के दल में अब 11 हाथी रह गए हैं। घटना के बाद से क्षेत्र में हाथियों की गतिविधियों को लेकर ग्रामीणों की चिंता और बढ़ गई है। हाथियों के लंबे समय से क्षेत्र में मौजूद रहने का सबसे अधिक असर किसानों की खेती पर पड़



रहा है। बिहारपुर क्षेत्र में हाथियों का दल अब तक सैकड़ों किसानों की धान सहित अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा चुका है। कहीं खेतों में खड़ी धान की फसल को हाथियों ने खाकर नष्ट किया तो कहीं फसलों को पैरों से रौंदकर चौपट कर दिया। किसानों की महीनों की मेहनत पर हाथियों के झुंड के कारण पानी फिर रहा है। धान की फसल तैयार होने और कटाई के समय हाथियों की आवाजाही से किसानों की चिंता और बढ़ गई है। वर्तमान में 11 जंगली हाथियों का दल छतरंग के आसपास के जंगलों में विचरण कर रहा है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के पार्क परिक्षेत्र के जंगलों में हाथियों की लगातार मौजूदगी बनी हुई है। जंगल से लगे गांवों के ग्रामीणों को खेतों और जंगल की ओर आने-जाने के दौरान विशेष सावधानी बरतनी पड़ रही है। ग्रामीणों को आशंका है कि हाथियों का दल कभी भी खेतों और आबादी वाले क्षेत्रों की ओर पहुंच सकता है।

लगातार फसल नुकसान झेल रहे किसानों के सामने अब आर्थिक संकट की स्थिति बन रही है। ग्रामीणों की मांग है कि वन विभाग हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखे और हाथियों की लोकेशन की जानकारी आसपास के गांवों में समय पर उपलब्ध कराए। साथ ही जिन किसानों की फसलों को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है, उनका मौके पर सर्वे कराकर नियमानुसार मुआवजा दिलाया जाए। चांदनी बिहारपुर जैसे पहाड़ी और वनांचल क्षेत्र में हाथियों की लगातार मौजूदगी ग्रामीणों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है।

भाजपा मंडल बिहारपुर कार्यसमिति बैठक संपन्न

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

चांदनी बिहारपुर। सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र में आज भाजपा मंडल बिहारपुर की कार्यसमिति बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाजपा के पदाधिकारी एवं क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक के



दौरान संगठन की मजबूती, पार्टी की आगामी कार्ययोजनाओं तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने सहित विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों और विचारधारा के अनुरूप क्षेत्र में सक्रिय रहकर संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने का आह्वान किया गया। बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने, आपसी समन्वय एवं एकजुटता के साथ कार्य करने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर भाजपा मंडल के पदाधिकारी एवं क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

दलहन, तिलहन और लघु धान्य फसलें समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएँगी, धान के साथ इनकी खेती अपनाने की अपील

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। किसानों की आय बढ़ाने और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन दलहन, तिलहन और लघु धान्य फसलों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य (खरीफ) पर कर रहा है। उद्देश्य इन फसलों का उत्पादन बढ़ाना है, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।

भारत सरकार की पीएम-आशा योजना के तहत खरीफ विपणन वर्ष 2026 में दलहन और तिलहन फसलों का उपार्जन समर्थन मूल्य पर होगा। प्रति क्विंटल दरें अरहर 8,450 रुपये, सोयाबीन 5,708 रुपये, उड़द 8,200 रुपये, मूंग 8,780 रुपये और मूंगफली 7,517 रुपये निर्धारित हैं। प्रदेश में कोदो, कुटकी और रागी जैसी पारंपरिक लघु धान्य फसलों की सरकारी खरीदी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इनकी खरीदी कोदो 3,200 रुपये, कुटकी 3,550 रुपये और रागी 5,205 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में चना 5,875 रुपये, मसूर 7,000 रुपये और सरसों 6,200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उपार्जित करने का प्रावधान है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे धान के साथ दलहन, तिलहन और लघु धान्य फसलों की खेती भी अपनाएँ। इससे फसल विविधीकरण बढ़ेगा, मिट्टी की उर्वरता सुधरेगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। खरीदी, पंजीयन और अन्य जानकारी के लिए किसान निकटतम कृषि विभाग कार्यालय, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या प्राथमिक सहकारी समिति से संपर्क कर सकते हैं।

चक्रवात अकवान के असर से बदला मौसम, बारिश से ठिठुरन बढ़ी

किसानों की बढ़ी चिंता, खेतों में पड़ी धान पर मंडराया संकट

छ.ग. फ्रंटलाइन अंबिकापुर। चक्रवात अकवान का असर अब उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी दिखना शुरू हो गया है। अंबिकापुर सहित सरगुजा संभाग में शुक्रवार सुबह से मौसम का मिजाज बदला हुआ था। दोपहर बाद बूंदाबांदी शुरू हुई जो शाम होते ही झमाझम बारिश में बदल गई। बारिश के साथ चल रही ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी। शाम 5 बजे तक अंबिकापुर में 7.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अकवान चक्रवात का असर शनिवार तक रहने की उम्मीद है। हालांकि यह अब कमजोर पड़ गया है। मध्यम बारिश व हवा चलने की उम्मीद है। मौसम में आए इस बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है।

खेतों में धान की फसल पककर तैयार है और कई स्थानों पर कटाई का काम भी चल रहा है। ऐसे में किसानों को फसल खराब होने का डर सता रहा है। वहीं धान खरीदी का कार्य चल रहा है। ऐसे में बारिश होने पर कटाई, फसल के सुरक्षित रखरखाव और धान खरीदी की तैयारियों पर असर पड़ सकता है।



सरगुजा में 50 प्रतिशत धान की कटाई बाकी

मौसम का बदला मिजाज किसानों के लिए नई परेशानी खड़ी कर सकता है। बारिश के कारण खेतों में तैयार धान की फसल को नुकसान पहुंचने के साथ ही कटाई का काम भी प्रभावित होने की आशंका है। सरगुजा में 50 प्रतिशत से अधिक धान की कटाई बाकी है। खेत व खलिहान में धान पड़े हैं। बारिश के कारण फसल खराब हो सकती है। ऐसे में धान के रेट व गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है। इससे किसानों को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। किसानों का कहना है कि धान पकने के बाद यदि खेत में ही पानी लग जाता है तो दाने में अंकुरण शुरू हो जाता है, जिससे धान की गुणवत्ता खराब हो जाती है। खलिहान में रखी धान भीगने से सड़ने का खतरा बढ़ जाता है। खरीदी केंद्रों में भी खुले में रखा धान भीगने की आशंका है।

मौसम साफ होते ही बढ़ेगी ठंड

मौसम वैज्ञानिक एसके मंडल ने बताया कि यह चक्रवात बंगाल की खाड़ी में 10 दिन पूर्व ही बना था। अब यह कमजोर पड़ गया है। इस दौरान उत्तरी छत्तीसगढ़ में मध्यम बारिश के साथ हवा चलने की आशंका है। वहीं मौसम साफ होते ही दो से तीन दिन बाद तापमान में भारी गिरावट आ सकती है। इससे सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि कटी हुई फसल को तिरपाल से ढककर रखें, खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करें और बारिश के दौरान कटाई व छिड़काव का काम न करें।

जिले में श्रद्धा भाव से मनाया गया देवउठनी एकादशी पर्व

- तुलसी-शालिग्राम का विवाह कराकर की गई पूजा, छोटी दिवाली जैसी रही रौनक, शुरू हुए मांगलिक कार्य

छ.ग. फ्रंटलाइन अंबिकापुर। नजिला मुख्यालय अंबिकापुर सहित पूरे संभाग में शुक्रवार को देवउठनी एकादशी पर्व श्रद्धा भाव से मनाया गया। श्रद्धालुओं ने गन्ने का मंडप बनाकर तुलसी की पूजा की। देवउठनी एकादशी के साथ ही मांगलिक कार्य प्रारंभ हो गए। देवउठनी एकादशी को सरगुजा में छोटी दिवाली के रूप में मनाते हैं। इसलिए बाजार में दिवाली की तरह रौनक रही।

पूरे दिन गन्ना, फूल माला व अन्य पूजा के सामान खरीदने लोगों की भीड़ लगी रही। लोगों ने दिवाली की तरह घरों की साफ-सफाई कर शाम को पूजा अर्चना की। इस दौरान लोगों ने अपने-अपने घरों के बाहर आकर्षक रंगोली भी बनाई। एक दिन पूर्व ही शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्र के किसान गन्ना लेकर पहुंचे थे। गन्ना 50-60 रुपए जोड़ी बिका। इसके अलावा फूल, माला की भी बिक्री जमकर हुई। वहीं देवउठनी एकादशी पर गन्ने के अलावा शकरकंद का भी विशेष महत्व है।



बदले मौसम के बीच हुआ आतिशी शोर-दिवाली के बाद पुन: छोटी दिवाली के रूप में देवउठनी एकादशी का इंतजार रहता है। देवउठनी एकादशी पर श्रद्धालुओं ने गन्ने का मंडप बनाकर तुलसी व शालिग्राम का विवाह कराया। इसके बाद पूरी रात दिवाली की तरह लोगों ने आतिशबाजी की। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने आतिशबाजी का आनंद लिया। शहर के चौक-चौराहों और मोहल्लों में देर रात तक चहल-पहल रही। घरों में दीप जलाए गए और प्रसाद वितरण किया गया।

मांगलिक कार्य शुरू

देवउठनी एकादशी के साथ मांगलिक कार्य शुरू हो गए। मान्यता है भगवान विष्णु 17 जुलाई से देवशयनी एकादशी पर योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए मांगलिक कार्य पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। इसके साथ ही शुभ मुहूर्त व मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। अब आने वाले दिनों में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। पंडितों के पास मुहूर्त पूछने वालों की भीड़ भी बढ़ने लगी है।

अवैध धान भंडारण के विरुद्ध कार्रवाई, 658 क्विंटल धान जब्त

खाद्य विभाग एवं मंडी की संयुक्त जांच दल ने चार ट्रेडर्स के प्रतिष्ठानों में की जांच, मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई



छ.ग. फ्रंटलाइन अंबिकापुर। जिले में धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने तथा अवैध धान के भंडारण और व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार जांच एवं निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में आज खाद्य विभाग एवं मंडी की संयुक्त जांच दल द्वारा अंबिकापुर एवं श्रीगढ़ स्थित विभिन्न ट्रेडर्स के प्रतिष्ठानों में जांच की गई। जांच के दौरान कुल 658 क्विंटल धान जब्त किया गया। संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर श्री अजीत वसंत के निर्देश पर खाद्य विभाग एवं मंडी की संयुक्त जांच दल द्वारा यह कार्रवाई की गई। जांच के दौरान कृष्णा ट्रेडिंग से 160 क्विंटल, महामाया ट्रेडिंग श्रीगढ़ से 158 क्विंटल, आदर्श ट्रेडिंग श्रीगढ़ से 140 क्विंटल तथा जे.के. ट्रेडिंग श्रीगढ़ से 200 क्विंटल धान जब्त किया गया। इस प्रकार चारों प्रतिष्ठानों से कुल 658 क्विंटल धान जब्त किया गया।

उन्होंने बताया कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान अवैध धान के भंडारण, परिवहन एवं व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए विभागीय टीम द्वारा लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है।

जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि धान खरीदी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा अवैध गतिविधि पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

नर्सों की अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित, आश्वासन के बाद काम पर लौटे

एक माह में आदेश नहीं हुआ तो फिर बनेगी आंदोलन की स्थिति

छ.ग. फ्रंटलाइन अंबिकापुर। नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ की अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित हो गई है। संघ ने 18 नवंबर से शुरू हुए आंदोलन को स्वास्थ्य मंत्री से हुई सार्थक चर्चा और मिले आश्वासन के बाद स्थगित करने का निर्णय लिया है। संघ की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रीना राजपूत ने 19 नवंबर को स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर आंदोलन स्थगित करने की जानकारी दी है। पत्र में संघ ने पूरे घटनाक्रम और आगे की रणनीति का भी उल्लेख किया है।

संघ की सरगुजा अध्यक्ष ने बताया कि आंदोलन के दूसरे दिन ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उन्हें चर्चा के लिए बुलाया गया। मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए मंत्री के आदेशानुसार संघ द्वारा डेली वेजेस और संविदा स्टाफ को तत्काल कार्यस्थल पर भेज दिया गया था, ताकि अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित न हों। संघ के अनुसार आयुक्त चिकित्सा शिक्षा महोदय द्वारा गठित कमेटी की अनुशंसा पर चर्चा उपरांत बनाए गए प्रस्ताव को शासन स्तर पर प्रेषित करने की बात हुई है। बजट प्रस्ताव को वित्त विभाग में भेजे जाने के आश्वासन उपरांत मंत्री के साथ हुई सार्थक चर्चा के आधार पर पदाधिकारियों की सहमति से



संघ ने अनिश्चितकालीन आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

संघ की प्रमुख मांगों में ग्रेड पे में सुधार, वेतनमान का निर्धारण, नर्सिंग अलाउंस और ड्रेस अलाउंस शामिल हैं। लंबे समय से नर्सिंग अधिकारी इन मांगों को लेकर शासन से गुहार लगा रहे थे। 2018 में गठित कमेटी की अनुशंसा के बाद भी आदेश जारी नहीं होने से नर्सिंग अधिकारियों में नाराजगी थी, जिसके चलते उन्होंने अनिश्चितकालीन आंदोलन का रास्ता अपनाया था। हालांकि संघ ने स्पष्ट यह भी स्पष्ट किया है कि यदि ग्रेड पे वेतनमान, नर्सिंग अलाउंस एवं ड्रेस अलाउंस हेतु आदेश जारी नहीं किए गए तो एक माह पश्चात अनिश्चितकालीन आंदोलन संघ द्वारा फिर से किया जाएगा। संघ ने स्वास्थ्य मंत्री से शीघ्रातिशीघ्र आदेश जारी करवाने हेतु उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

भर्ती मरीजों को मिलेगी राहत

हड़ताल स्थगित होने से प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को राहत मिलेगी। पिछले दो दिनों से हड़ताल के कारण जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही थीं। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल सहित सरगुजा संभाग के अन्य अस्पतालों में भी मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नर्सिंग स्टाफ के काम पर लौटने से अब अस्पतालों में व्यवस्था धीरे-धीरे सामान्य होने की उम्मीद है। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि वे मरीजों की सेवा को सर्वोपरि मानते हैं, इसलिए उन्होंने सरकार के आश्वासन पर भरोसा करके आंदोलन स्थगित किया है। इसके पहले तीन दिवसीय स्थानीय स्तर पर आंदोलन के बाद शनिवार को रायपुर रवाना होने की रणनीति बनी थी। अब सबकी नजर शासन के अगले कदम पर टिकी है।

धान खरीदी और आदान सहायता से किसानों को मिलेगा आर्थिक संबल, किसान अर्जुन राम राजवाड़े ने मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार

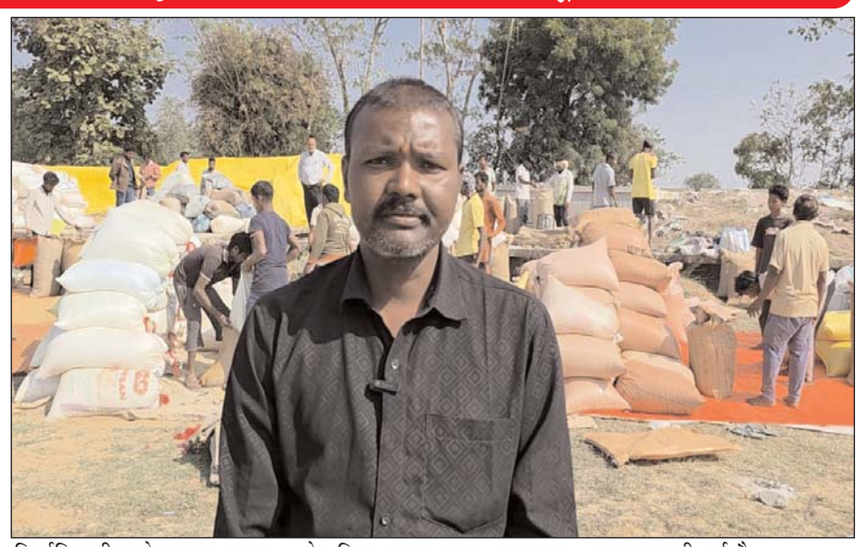
21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचने पर भी किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत मिलेगी पूरी आदान सहायता राशि

- सरगुजा जिले के 61 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की व्यवस्था, 62 हजार 471 किसानों का पंजीयन
- 3,100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी और 13,839 प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता

छ.ग. फ्रंटलाइन अंबिकापुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों के हित में लिए गए निर्णयों से किसानों को आर्थिक संबल मिल रहा है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के साथ आदान सहायता की व्यवस्था ने किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। शासन द्वारा 3,100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है। इसके साथ ही 13,839 प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता प्रदान की जा रही है। उल्लेखनीय है कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचने वाले किसानों को भी पूरी आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा।

रामपुर धान उपार्जन केंद्र में धान विक्रय करने पहुंचे ग्राम नवाबांध निवासी किसान श्री अर्जुन राम राजवाड़े ने शासन की इस व्यवस्था की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि वे आज अपना धान बेचने के लिए रामपुर मंडी पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के साथ अंतर की राशि के रूप में आदान सहायता प्रदान करने का निर्णय बहुत अच्छी पहल है।

श्री राजवाड़े ने कहा कि पहले अंतर की राशि को लेकर बिचैलियों द्वारा किसानों को बहला-फुसलाकर कम पैसे देकर उनका आर्थिक शोषण किया जाता था। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती थी और उन्हें अपनी उपज का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता था। अब शासन द्वारा किसानों के हित में सीधे निर्णय लेकर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे किसानों को राहत मिल रही है। उन्होंने कहा कि पहले जिन किसानों का उत्पादन 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम होता था, वे



निर्धारित सीमा के कारण अपना पूरा धान समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाते थे। ऐसी स्थिति में किसानों को शेष धान व्यापारियों को बेचना पड़ता था। वर्तमान व्यवस्था में 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान विक्रय करने वाले किसानों को भी पूरी आदान सहायता राशि देने का निर्णय किसानों के हित में सराहनीय कदम है।

किसान श्री राजवाड़े ने कहा कि शासन की इस पहल से किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य और अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिल रही है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तथा खेती-किसानी को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को किसान हितैषी निर्णयों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दिया।

सरगुजा जिले में 61 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत सरगुजा जिले में धान खरीदी के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। जिले में कुल 62 हजार 471 किसानों ने धान विक्रय के लिए पंजीयन कराया है। इन किसानों का कुल पंजीकृत कृषि रकबा 67 हजार 929.40 हेक्टेयर है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिले में पूर्व से संचालित 54 उपार्जन केंद्रों के अतिरिक्त 7 नवीन उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। इस प्रकार जिले में कुल 61 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की व्यवस्था की गई है।

पारदर्शी और सुविधाजनक धान खरीदी व्यवस्था

राज्य शासन द्वारा 15 नवंबर 2026 से जिले के सभी 61 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी प्रारंभ की गई है। किसानों से 3,100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जा रहा है। इसके साथ ही कृषक उन्नति योजना के तहत 13,839 प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता दी जा रही है। धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली लागू की गई है। वहीं, किसानों की सुविधा के लिए शुंतहर टोकन ऐपश् के माध्यम से घर बैठे 24 घंटे टोकन प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक- मनीष पाठक द्वारा स्पीड प्रिंटर्स व आफसेट पुराना पोस्ट ऑफीस रोड दरीपारा अम्बिकापुर पिन नं. 497001 (छत्तीसगढ़) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-रणविजय सिंह तोमर